RNI No.: UPHIN/25/A1698
NAVSARJAN SANSKRUTI
नवसर्जन संस्कृति
नवसर्जन संस्कृति
लखनऊ से प्रकाशित दैनिक
वर्ष : 02
अंक : 002
दि. 02.05.2026, शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

बंगाल में 4 मई काउंटिंग से पहले विवाद, केंद्र कर्मी गिनेंगे वोट? टीएमसी ने चुनाव आयोग को कोर्ट में घेरा! आज सुनवाई

(जीएनएस)।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना से ठीक दो दिन पहले तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग के एक विवादित निर्देश को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पार्टी ने एउ के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें 4 मई को होने वाली मतगणना के हर टेबल पर काउंटिंग सुपरवाइजर और सहायक के रूप में केवल केंद्र सरकार या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) के कर्मचारियों को नियुक्त करने का आदेश दिया गया है।

ळटउ ने तत्काल सुनवाई की मांग की है। शनिवार (2 मई) को सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर विशेष पीठ के सामने सुनवाई करेगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार (30 अप्रैल) को ळटउ की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। अब शीर्ष अदालत में यह मामला पहुंच गया है, जिससे 4 मई की मतगणना से पहले राजनीतिक तापमान और बढ़ गया है।

13 अप्रैल 2026 को जारी एउ के आदेश में साफ लिखा गया था कि प्रत्येक मतगणना केंद्र पर मतगणना पर्यवेक्षक और मतगणना सहायक में से कम से कम एक केंद्र सरकार या केंद्रीय PSU का कर्मचारी होना अनिवार्य है। TMC का आरोप है कि यह निर्देश बिना किसी ठोस कारण या मानदंड के जारी किया गया। इससे मतगणना केंद्रों पर कर्मचारियों की संरचना में 'बड़ा बदलाव' होगा। पहले से ही माइक्रो-ऑब्जर्वर केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं। अब अतिरिक्त काउंटिंग सुपरवाइजर और सहायक भी केंद्र के नियंत्रण में आएंगे।

TMC ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका में कहा कि यह आदेश पक्षपात की उचित आशंका पैदा करता है। मतगणना की निष्पक्षता कमजोर होती है। चुनाव लड़ने वाले दलों के बीच समान अवसर बाधित होते हैं। पार्टी ने स्पष्ट रूप से लिखा कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) केंद्र में सत्तारूढ़ दल है, इसलिए केंद्रीय सरकार/ढरव के कर्मचारियों पर उसका प्रशासनिक नियंत्रण है। इससे 'संरचनात्मक पूर्वाग्रह' का खतरा है। याचिका में कहा गया कि एउ का यह कदम निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत के खिलाफ है। TMC ने 2023 की EC गाइडलाइंस का हवाला दिया, जिसमें पहले से ही सूक्ष्म पर्यवेक्षक केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं। अब अतिरिक्त परत जोड़ने से 'असंतुलन' बढ़ेगा।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्यों खारिज किया? 30 अप्रैल को कलकत्ता हाईकोर्ट ने TMC की याचिका खारिज करते हुए कहा कि पक्षपात की आशंका को 'विश्वास करना असंभव' है।'

कोर्ट ने पार्टी को सलाह दी कि वह नतीजे आने के बाद चुनाव याचिका (ए'ी३ङ्क्ल्ल ढी३३ङ्क्ल्ल) के जरिए चुनौती दे सकती है। हाईकोर्ट ने एउ के विशेषाधिकार को बरकरार रखा और कहा कि अदालत को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। ळटउ ने हाईकोर्ट के इस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा? कौन-कौन पैरवी करेगा?

ळटउ की याचिका पर न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ सुनवाई करेगी। याचिका अधिवक्ता संचित गर्ग ने दायर की है। ळटउ की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल समेत अन्य सीनियर वकील पैरवी करेंगे। TMC ने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत की मांग की है – यानी एउ के आदेश पर तत्काल रोक लगाई जाए ताकि मतगणना निष्पक्ष तरीके से हो सके।

पश्चिम बंगाल का राजनीतिक संदर्भ: टीएमसी-भाजपा की जानी-पहचानी जंग

पश्चिम बंगाल में TMC और BJP के बीच लंबे समय से तीखी सियासी लड़ाई चल रही है। 2021 विधानसभा चुनाव से लेकर हाल के उप-चुनावों तक दोनों पार्टियां एक-दूसरे पर 'वोट चोरी' और 'पक्षपात' के आरोप लगाती रही हैं। ळटउ का मानना है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बड़ी संख्या से इखढ को फायदा हो सकता है। एउ ने अपने आदेश में सुरक्षा और निष्पक्षता का हवाला दिया था, लेकिन ळटउ इसे 'राजनीतिक दखल' मान रही है।

अगर सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है?

Stay दे सकता है: EC के आदेश पर रोक लगाकर राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी बराबर मौका दे सकता है।

निर्देश दे सकता है: EC को वैकल्पिक व्यवस्था बनाने को कह सकता है।

खारिज कर सकता है: TMC की याचिका को खारिज कर एउ के फैसले को बरकरार रख सकता है।

जो भी फैसला हो, यह 4 मई की मतगणना पर सीधा असर डालेगा। पश्चिम बंगाल में सैकड़ों मतगणना केंद्रों पर हजारों कर्मचारी तैनात हैं। कोई भी बदलाव लास्ट-मिनट में लॉजिस्टिक चुनौती पैदा कर सकता है।

चुनाव आयोग की भूमिका और संवैधानिक सवाल

एउक का काम निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करना है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत उसे व्यापक शक्तियां हैं। लेकिन TMC का कहना है कि यह शक्ति 'पक्षपात रहित' होनी चाहिए। यह मामला चुनावी निष्पक्षता और संस्थागत विश्वास का बड़ा सवाल उठाता है। पिछले कई चुनावों में भी काउंटिंग एजेंटों को लेकर विवाद हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट कई बार एउ के फैसलों की समीक्षा कर चुका है।

TMC का अगला कदम और राजनीतिक नतीजे

TMC ने साफ कहा है कि वह मतगणना की निष्पक्षता के लिए हर कानूनी रास्ता आजमाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट राहत देता है तो ळटउ के लिए यह बड़ी जीत होगी। अगर नहीं, तो पार्टी नतीजों के बाद चुनाव याचिका दायर करेगी। यह मामला सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं। देशभर के विपक्षी दल इसे 'केंद्र ५२ राज्य' की लड़ाई के रूप में देख रहे हैं।

4 मई को पश्चिम बंगाल में मतगणना होनी है। TMC की याचिका पर शनिवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना तय है। यह फैसला न सिर्फ इस चुनाव की निष्पक्षता, बल्कि भविष्य के चुनावों में EC की भूमिका पर भी असर डालेगा। क्या शीर्ष अदालत TMC की चिंताओं को दूर करेगी या EC के अधिकार को बरकरार रखेगी? पूरी राजनीतिक और कानूनी नजर इस सुनवाई पर टिकी हुई है।

ईवीएम-बैलट बॉक्स के साथ नहीं होगी गड़बड़ी! क्यूआर कोड से होगी एंट्री, टीएमसी के आरोप पर चुनाव आयोग ने क्या कहा?

(जीएनएस)।

मतगणना से ठीक पहले चुनावी माहौल सिर्फ वोटों की गिनती तक सीमित नहीं है। पश्चिम बंगाल में स्ट्रॉन्गरूम को लेकर उठे सवाल, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौके पर मौजूदगी और चुनाव आयोग की नई सुरक्षा व्यवस्था ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस ने पोस्टल बैलट और स्ट्रॉन्गरूम की सुरक्षा पर सवाल उठाए, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने साफ किया कि पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत चल रही है।

इसी बीच चुनाव आयोग ने मतगणना केंद्रों (काउंटिंग सेंटर) की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब काउंटिंग सेंटर में एंट्री के लिए दफ उङ्गी आधारित फोटो पहचान पत्र लागू किया जा रहा है। यह नई व्यवस्था पहली बार 4 मई 2026 को होने वाली मतगणना में लागू होगी।

चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि अब मतगणना केंद्रों पर पुराने ढर्रे से काम नहीं चलेगा। 4 मई 2026 को होने वाली असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी की विधानसभा चुनाव की मतगणना के साथ ही यह नया नियम लागू हो जाएगा। इसके तहत चुनाव आयोग के एउक्ठएळ पोर्टल पर एक खास दफ कोड आधारित फोटो आईडी कार्ड मॉड्यूल तैयार किया गया है।

इस व्यवस्था को लागू करने के लिए 'थ्री-टियर' (तीन स्तरीय) सुरक्षा घेरा बनाया गया है। पहले और दूसरे घेरे पर चुनाव अधिकारी (RO) द्वारा जारी किए गए कार्ड की मैन्युअल चेकिंग होगी। असली खेल तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण घेरे में होगा। मतगणना हॉल के ठीक बाहर डिजिटल स्कैनर लगे होंगे। जब तक आपका QR कोड वहां मौजूद डेटा से मैच नहीं करेगा, तब तक गेट नहीं खुलेगा। यह नियम सिर्फ कर्मचारियों के लिए ही नहीं, बल्कि उम्मीदवारों, उनके एजेंटों और तकनीकी स्टाफ के लिए भी अनिवार्य होगा।

श्री आशुतोष गोवारिकर को 57वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए महोत्सव निदेशक नियुक्त किया गया है

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने गोवा में आयोजित होने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) के 57वें संस्करण के लिए प्रख्यात फिल्म निमार्ता श्री आशुतोष गोवारिकर को महोत्सव निदेशक नियुक्त किया है।

श्री गोवारिकर एक प्रख्यात फिल्म निमार्ता हैं जिन्होंने भारतीय सिनेमा में विशिष्ट योगदान दिया है। आईएफएफआई के साथ उनका जुड़ाव कई दशकों से है, जो सिनेमाई कलाओं और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म संस्कृति के विकास के प्रति उनकी गहरी रुचि को दशार्ता है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने लद्दाख में विभिन्न डेयरी अवसंरचना एवं सहकारी पहलों का शिलान्यास और उद्घाटन किया

(जीएनएस)।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज लद्दाख के लेह में केन्द्रशासित प्रदेश के लिए विभिन्न डेयरी अवसंरचना एवं सहकारी पहलों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री श्री एस पी सिंह बघेल एवं श्री जॉर्ज कुरियन तथा लद्दाख के उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना भी उपस्थित थे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा दिए गए सहकारिता मॉडल के तहत आज लद्दाख में ढेर सारे कार्यक्रम एक साथ हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज करगिल जैसी ऊंची जगह पर 10 टीएलपीडी क्षमता वाले डेयरी प्लांट का शिलान्यास हुआ है, जिसकी क्षमता 10,000 लीटर दूध प्रतिदिन प्रोसेस करने की है। करगिल की महिलाएं डेयरी प्लांट के माध्यम से अपने जीवन में उजाला ला सकती हैं, परिवार की मदद कर सकती हैं और आत्मनिर्भर भी बना सकती हैं। श्री शाह ने कहा कि वे एक ऐसे प्रदेश से आते हैं जहाँ की महिलाओं ने ऐसी ही छोटी-छोटी डेयरियों के माध्यम से 1,25,000 करोड़ रुपये का टर्नओवर हासिल किया है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से इतनी संभावना है कि यहां की महिलाएं अपने परिवार और बच्चों की अच्छी पढ़ाई-लिखाई में योगदान कर सकें। श्री शाह ने कहा कि 25 करोड़ की लागत से जिस नई परियोजना की शुरूआत होने जा रही है, वह निश्चित रूप से करगिल की माताओं-बहनों के लिए शुभंकर साबित होगी। सहकारिता मंत्री ने कहा कि लेह में पहले से काम कर रहे मिल्क प्लांट में प्रतिदिन उत्पादन की व्यवस्था शुरू हो रही है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि लद्दाख में आईटीबीपी और सेना बहुत बड़े खरीददार हैं। यहां सीमा पर 18,000 जवान रहते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि आईटीबीपी और सेना की दूध, दही और पनीर की जरूरत इस प्लांट से पूरी होगी। श्री शाह ने कहा कि 45 लाख रुपए की लागत से एक मोबाइल प्रयोगशाला भी लॉन्च की गई है, जिससे दूध की क्वालिटी के रखरखाव में बहुत फायदा होगा। उन्होंने कहा कि एंड्रॉइड आधारित अटउर ऐप का शुभारंभ भी हुआ है, जिससे हमारे दुग्ध उत्पादक पशुपालक पारदर्शिता के साथ अपने दूध का हिसाब-किताब एक ही ऐप पर देख पाएंगे। इससे दुग्ध उत्पादक पशुपालकों के मन में आत्मविश्वास भी जागृत होगा। उन्होंने कहा कि आज जिन पाँच पशुपालकों को पुरस्कृत किया गया वे करगिल और लेह के सभी पशुपालकों के लिए प्रेरणा का रूप हैं।

श्री अमित शाह ने कहा कि लद्दाख मिल्क फेडरेशन और मदर डेयरी ने एक समझौता किया है। इससे लद्दाख को देश के बाजार के साथ जोड़ने की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने कहा कि लद्दाख के ऑर्गेनिक उत्पादों को दिल्ली का बड़ा बाजार मिलना चाहिए। श्री शाह ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) से आग्रह किया कि वह इसके लिए नॅशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड को साथ लेकर एक त्रिपक्षीय एमओयू करें। उन्होंने कहा कि मदर डेयरी के प्रोडक्ट तो यहां बेचे ही जाएं, साथ ही मदर डेयरी अन्य सहकारी संस्थाओं के माध्यम से यहां के प्रोडक्ट की भी देश भर में मार्केटिंग की व्यवस्था करे।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि हम लद्दाख में डेयरी अवसंरचना का विस्तार करने जा रहे हैं। लेह में आने वाले दिनों में 70 करोड़ रुपए की लागत से 50,000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला एक नया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। वह लेह में बढ़ने वाली संभावनाओं का तो दोहन करेगा ही, साथ ही करगिल में लगाए जा रहे संयंत्र से दूध बढ़ने पर दोनों क्षेत्रों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। यहां के मौसम के अनुरूप अच्छी नस्ल की गाय और भैंस उपलब्ध कराने का काम होगा। लगभग हर साल अच्छी नस्ल की 500 गाय और भैंसे यहां उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे दूध का उत्पादन बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि लद्दाख काफी ठंडा प्रदेश है, यहां ऑक्सीजन की भी कमी होती है। इसलिए रिसर्च करके यहाँ के मौसम में ढल सकने वाले पशु स्थानीय लोगों को दिए जाएंगे। श्री शाह ने कहा कि आगामी 10 साल में पशुओं की संख्या में लगभग तीन गुनी बढ़ोतरी करने की योजना है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस योजना को लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। श्री शाह ने कहा कि लद्दाख मिल्क फेडरेशन और एनडीडीबी में समझौता होने के बाद यह नेटवर्क 28 गांवों तक पहुंचा है और लगभग 1700 दुग्ध उत्पादक इससे जुड़े हैं। उन्होंने एनडीडीबी के अध्यक्ष से कहा कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा गांवों में, जहां पशुपालन संभव हो, वहां एनडीडीबी की पहुँच होनी चाहिए और उन्हें इन सभी पशुपालकों के जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि यहाँ दैनिक दूध की खरीद लगभग 7000 किलोलीटर तक पहुंची है।

लेबर डे पर नोएडा में हाई अलर्ट! 8 मई तक धारा 163 लागू, ड्रोन से होगी निगरानी

(जीएनएस)।

अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर नोएडा प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। हाल ही में फैक्ट्री मजदूरों द्वारा किए गए हिंसक विरोध प्रदर्शनों और उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए पूरे जिले को एक अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है।

शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (इठरर) की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) को पूरे जिले में 8 मई 2026 तक लागू कर दिया है।

आसमान से ड्रोन और जमीन पर 1600 से अधिक जवान

मजदूर दिवस पर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए नोएडा पुलिस ने तकनीकी और शारीरिक सुरक्षा का अनूठा तालमेल बिठाया है:

ड्रोन निगरानी: जिले के 50 से अधिक संवेदनशील स्थानों और प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों पर ड्रोन के जरिए आसमान से नजर रखी जा रही है। विशेष रूप से फेज-2, सेक्टर-59 और सेक्टर-60 जैसे औद्योगिक इलाकों में सघन निगरानी जारी है।

भारी पुलिस बल की तैनाती: सुरक्षा के लिए 1,600 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इसमें 6 एसपी रैंक के अधिकारी, 14 अतिरिक्त एसपी, 30 एसीपी, और 1100 से अधिक कांस्टेबल शामिल हैं। इसके अलावा ढअउ की 10 कंपनियां भी संवेदनशील इलाकों में गश्त कर रही हैं।

जोन और सेक्टर स्कीम: पूरे जिले को 11 जोन और 49 सेक्टरों में बांटा गया है। नोएडा जोन में 4 जोन और 16 सेक्टर, जबकि सेंट्रल नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी इसी तरह का सुरक्षा ढांचा तैयार किया गया है।

Section 163 BNSS लागू: इन बातों का रखना होगा ध्यान

पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक, 8 मई तक कुछ प्रतिबंध कड़ाई से लागू रहेंगे:

सार्वजनिक स्थानों पर 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध है।

बिना पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार का जुलूस या विरोध प्रदर्शन नहीं निकाला जा सकेगा।

सरकारी कार्यालयों के एक किलोमीटर के दायरे में 'नो-फ्लाई जोन' घोषित किया गया है, यानी यहाँ निजी ड्रोन नहीं उड़ाए जा सकेंगे।

सोशल मीडिया पर भ्रामक या भड़काऊ पोस्ट डालने वालों पर साइबर सेल की पैनी नजर है।

पुलिस कमिश्नर की खास अपील: 'शांति और व्यवस्था कायम'

गौतमबुद्धनगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने स्थिति का जायजा लेते हुए कहा, "विभिन्न श्रमिक संगठनों द्वारा पारंपरिक रूप से आयोजित कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं। वर्तमान में हर जगह शांति है और सभी औद्योगिक इकाइयों में काम सुचारू रूप से चल रहा है। हमारी टीमें जमीन पर सक्रिय हैं और हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं।"

पिछली हिंसा से लिया सबक

गौरतलब है कि 13 अप्रैल को न्यूनतम मजदूरी को लेकर हुए श्रमिकों के प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया था, जिसमें आगजनी और तोड़फोड़ की खबरें आई थीं। उस घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए इस बार पुलिस ने 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई है। कंट्रोल रूम में तैनात राजपत्रित अधिकारी सीसीटीवी फीड के जरिए पल-पल की निगरानी कर रहे हैं।

पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो बैरियर-रहित टोलिंग सिस्टम लॉन्च

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 के सूरत-भरूच खंड पर स्थित चोरायासी टोल प्लाजा पर भारत की पहली मल्टी-लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) बाधा रहित (बैरियर-लेस) टोलिंग प्रणाली के शुभारंभ की घोषणा की। यह अत्याधुनिक प्रणाली ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) और FASTag जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करके, वाहनों को बिना रुके निर्बाध टोल संग्रह की सुविधा प्रदान करती है।

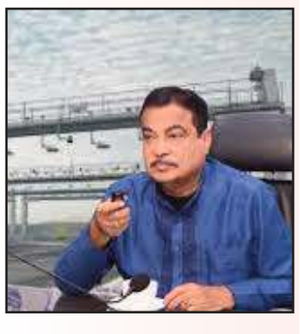

एमएलएफएफ की शुरूआत भारत के टोलिंग इकोसिस्टम के डिजिटलीकरण और वैश्विक मानकों के अनुरूप राष्ट्रीय राजमार्ग बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण में एक बड़ा मील का पत्थर है। इस प्रणाली से यात्रा के समय में काफी कमी आने, राजमार्गों पर भीड़ कम होने, ईंधन दक्षता में सुधार होने, वाहनों के उत्सर्जन में कमी आने और टोल संचालन में मानवीय हस्तक्षेप कम होने की उम्मीद है।

श्री गडकरी ने कहा कि बाधा रहित टोलिंग नागरिकों के लिए 'ईज ऑफ लिविंग' (जीवन सुगमता) को बढ़ाएगी और देशभर में माल और लॉजिस्टिक्स की तेज एवं अधिक कुशल आवाजाही सुनिश्चित कर 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (व्यापार सुगमता) को बढ़ावा देगी।

लखनऊः नारी आक्रोश यात्रा कल, हजरतगंज के इन हिस्सों में बदली रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था; जानिए कहां होगी नो एंट्री

लखनऊ

नारी आक्रोश मशाल यात्रा के कारण शनिवार को हजरतगंज इलाके में यातायात बदला रहेगा। दिन में तीन बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक आवागमन में बदलाव किया गया है। इमरजेंसी की स्थिति में पुलिस स्कूली वाहन, शव वाहन, एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड को निकलवाएगी।

– लाल बत्ती चौराहा की ओर से 1090 चौराहा, समतामूलक चौराहा, पॉलीटेक्निक चौराहा, सुभाष चौराहा चौक की ओर जाने वाला सामान्य यातायात हजरतगंज की ओर प्रतिबंधित रहेगा। यह लालबत्ती चौराहा से जी 20 चौराहा, कमता तिराहा होकर जाएगा।

– डीएसओ चौराहा, रॉयल होटल चौराहा की ओर से सिकंदरबाग चौराहा, महानगर, गोमतीनगर की ओर जाने वाला सामान्य यातायात हजरतगंज की ओर प्रतिबंधित रहेगा। यह लालबत्ती चौराहा से जी 20 चौराहा, कमता तिराहा होकर जाएगा।

– पार्क रोड की ओर से चारबाग, कैसरबाग, लालबत्ती की ओर जाने वाला सामान्य यातायात हजरतगंज में प्रतिबंधित रहेगा। यह पार्क रोड से सिकंदरबाग चौराहा, चिरैयाझील चौराहा, सुभाष चौराहा की ओर से

जाएगा।

– गोमतीनगर की ओर से कैंट, चारबाग, आलमबाग, चौक की ओर जाने वाला सामान्य यातायात हजरतगंज चौराहा की ओर नहीं जा सकेगा। यह यातायात समतामूलक चौराहा से ग्रीन कारिडोर होकर डालीगंज चौराहा होकर जा सकेगा।

– सिकंदरबाग चौराहा की ओर से चारबाग, चौक, कैसरबाग की ओर जाने वाला सामान्य यातायात हजरतगंज की ओर नहीं जा सकेगा। यह सुशीला स्मृतिका ग्रीन कॉरिडोर चौराहा होकर ग्रीन कारिडोर, डालीगंज चौराहा होकर जा सकेगा।

– परिवर्तन चौक, हिंदी संस्थान तिराहा की ओर से गोमतीनगर, कैंट, अर्जुनगंज, तेलीबाग कानपुर रोड की ओर जाने वाला सामान्य यातायात हजरतगंज चौराहा की ओर नहीं जा सकेगा। यह सुभाष चौराहा से ग्रीन कॉरिडोर या चिरैयाझील होकर जा सकेगा।

– तेलीबाग / बंगलाबाजार से गोमतीनगर / महानगर की ओर जाने वाला सामान्य यातायात डीएसओ चौराहा /हजतरगंज की ओर प्रतिबंधित रहेगा, बल्कि यह यातायात बन्दरियाबाग चौराहा / गोल्फ क्लब चौराहा / 1090 चौराहा / समतामूलक चौराहा होकर जा सकेगा।

– लालबाग चौराहा से महानगर, गोमतीनगर, कैंट की ओर जाने वाला सामान्य यातायात कैपिटल तिराहा की तरफ प्रतिबंधित रहेगा। यह मेफेयर तिराहा, सुभाष चौराहा, अल्का तिराहा, डनलप तिराहा, सिकंदरबाग चौराहा, ग्रीन कॉरिडोर होकर जा सकेगा। – चारबाग से महानगर, गोमतीनगर की ओर जाने वाला सामान्य यातायात बलिंग्टन चौराहा से बाएं अशोक लाट चौराहा होते हुए सुभाष चौराहा, हनुमान सेतु होकर जा सकेगा।

रायन इंटरनेशनल स्कूल, चेंबूर ने फिर से रचे शैक्षणिक उत्कृष्टता के नये प्रतिमान

मुंबई, 1 मई। मुंबई के प्रमुख शिक्षा संस्थान रायन इंटरनेशनल स्कूल, चेंबूर ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए आईसीएसई परीक्षा में अपने विद्यार्थियों की असाधारण उपलब्धियों की बदौलत शैक्षणिक उत्कृष्टता के नये प्रतिमान रचते हुए एक बार फि र से शानदार सफलता का परचम लहराया है।

यह जानकारी देते हुए रायन इंटरनेशनल स्कूल की वरिष्ठ शिक्षिका तथा मुंबई की सुपरिचित साहित्यकार श्रीमती प्रमिला शर्मा ने बताया कि शैक्षणिक वर्ष 2025-26 की दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में रायन इंटर नेशनल स्कूल, चेम्बूर का परीक्षा परिणाम शत प्रतिशत रहा है। परिणाम घोषित होने पर विद्यालय में समारोहपूर्वक खुशियाँ मनाईं गईं। उन्होंने बताया कि रायन इंटरनेशनल स्कूल, चेंबूर ने हाल ही में हुई परीक्षाओं में 100% रिजल्ट पाकर गर्व महसूस किया है, जो एकेडमिक एक्सीलेंस के उसके सफर में एक और मील का पत्थर है। उन्होंने बताया कि यह शानदार उपलब्धि स्कूल के होलिस्टिक एजुकेशन, डिसिप्लिन्ड लर्निंग और लगातार एकेडमिक सपोर्ट के लिए पक्के कमिटमेंट को दिखाती है। मेधावी और सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों के इस ग्रुप को लीड करते हुए अनन्या श्रीकांत ने शानदार 99.40% हासिल किये। उसके बाद स्वरा प्रशांत शिंदे ने 98.60% अंक प्राप्त किये। उन्होंने कहा कि स्कूल को ऋषभ बनर्जी, कविश अमित परमार और मानित हेमल गांधी के शानदार परफॉर्मेंस पर भी बहुत गर्व है, जिन्होंने 97 % अंक स्कोर करके खुद को टॉप अचीवर्स में शामिल किया है। यह ओवर ऑल रिजल्ट एनालिसिस स्कूल के मजबूत एकेडमिक परफॉर्मेंस को बखूबी दिखाता है। उन्होंने बताया कि कुल 14 स्टूडेंट्स ने 95% से ज्यादा स्कोर किया, जबकि 64 स्टूडेंट्स ने 85% और 94% के बीच स्कोर किया। इसके अलावा, 48 स्टूडेंट्स ने 75% से 84% तक मार्क्स हासिल किए, और 15 स्टूडेंट्स ने 60% से 74% के बीच स्कोर किया। खास बात यह है कि किसी भी स्टूडेंट ने 60% से कम स्कोर नहीं किया, जो इंस्टीट्यूशन के लगातार बेहतरीन एकेडमिक स्टैंडर्ड को दशार्ता है। एग्जाम देने वाले कुल स्टूडेंट्स की संख्या 141 थी। उन्होंने कहा कि यह शानदार कामयाबी स्टूडेंट्स की लगन और कड़ी मेहनत का पुख़्ता सबूत है। साथ ही यह स्कूल की बहुत ही समर्पित फैकल्टी की लगातार कोशिशों को भी दिखाता है, जिनके गाइडेंस और मेंटरशिप ने इन सफलताओं को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। उनका मानना है कि माता- पिता से लगातार हिम्मत और सपोर्ट ने इस कामयाबी को और मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि हमारे छात्र-छात्राओं की सफलता हमारी सम्माननीय प्रबंधन टीम के अथक प्रयासों और समर्पण का भी प्रमाण है। विद्यार्थियों की प्रतिभा को पोषित करने में दूरदर्शी नेतृत्व और अटूट समर्थन के लिए अध्यक्ष डॉ. ए. एफ. पिंटो और प्रबंध निदेशक ग्रेस पिंटो का योगदान अतुलनीय रहा है। विद्यालय के चेयरमैन ने सभी विद्यार्थियों को बधाइयाँ देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ प्रकट की हैं। उन्होंने कहा कि चेंबूर के रायन इंटरनेशनल स्कूल में, हम युवा दिमागों को न केवल एकेडमिक रूप से बल्कि कैरेक्टर और वैल्यूज में भी बेहतरीन बनाने में यकीन रखते हैं।

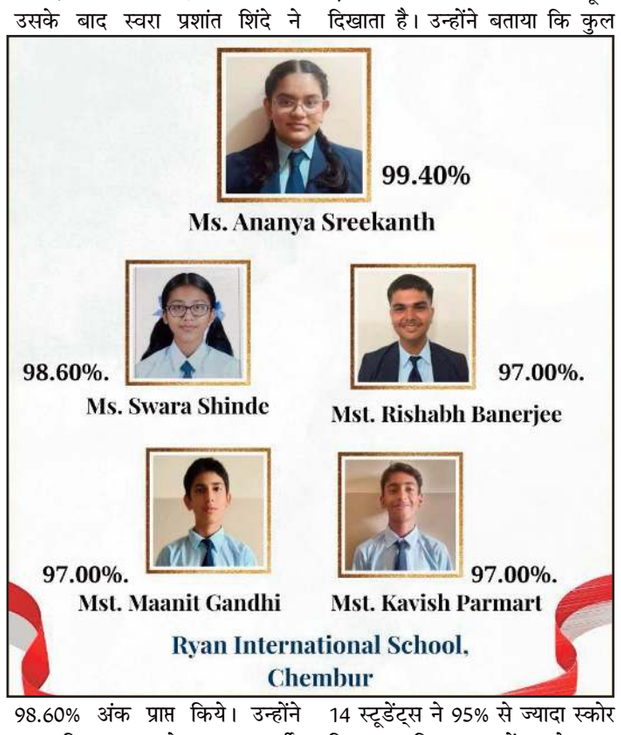

₹5 तक पेट्रोल-डीजल और ₹50 घरेलू एलपीजी बढ़ोतरी के संकेत? भारत में ईंधन होगा महंगा?

(जीएनएस)।

देश के करोड़ों वाहन मालिकों, घरेलू गैस उपभोक्ताओं और ट्रांसपोर्ट कारोबारियों के लिए चिंता की खबर। पेट्रोल-डीजल की कीमतों में ₹4 से ₹5 प्रति लीटर और घरेलू 14.2 किलो एलपीजी सिलेंडर में ₹40 से ₹50 तक की बढ़ोतरी का गंभीर संकेत मिल रहा है। अगर यह फैसला हो गया, तो यह लगभग चार साल बाद ईंधन कीमतों में पहली बड़ी वृद्धि होगी। 2022 के बाद से पेट्रोल-डीजल की खुदरा कीमतें लगभग स्थिर रहीं थीं।

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के संकेत इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के हवाले से सुर्खियों में आए। इसके बाद, सोशल मीडिया में खलबली मच गई है। आज 1 मई 2026 को कीमतें अभी भी स्थिर हैं, लेकिन तेल कंपनियों का घाटा बढ़ने और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के चलते सरकार 5-7 दिनों के अंदर अंतिम निर्णय ले सकती है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्पष्ट किया कि भारत इस संकट का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन आम आदमी के बजट पर असर पड़ना तय है...

देशभर में पेट्रोल-डीजल की कीमतें आज अपरिवर्तित हैं:

दिल्लीः पेट्रोल ₹94.77/लीटर, डीजल ₹87.67/लीटर

मुंबईः पेट्रोल ₹103.54/लीटर, डीजल ₹90.03/लीटर

कोलकाताः पेट्रोल ₹105.45/लीटर

चेन्नईः पेट्रोल ₹101.23/लीटर

घरेलू एलपीजी (14.2 किलो) की कीमत दिल्ली-मुंबई में ₹912-913 के आसपास है। हालांकि, 1 मई को भारत ने कमर्शियल छढऋसिलेंडर की कीमतों में ₹994 की भारी बढ़ोतरी की घोषणा की। इससे अब कमर्शियल सिलेंडर की दिल्ली में कीमत ₹3,071.50 हो गई है। पहले ये ₹2078.50 में मिल रहा था। मतलब साफ है कि रेस्टोरेंट, सड़क किनारे के ढाबे, कैटरर्स, बेकरी और क्लाउड किचन, छोटे व्यवसायों के उस अदृश्य नेटवर्क में चिंता की लहर दौड़ गई है, जो हर दिन भारतीयों का पेट भरता है।

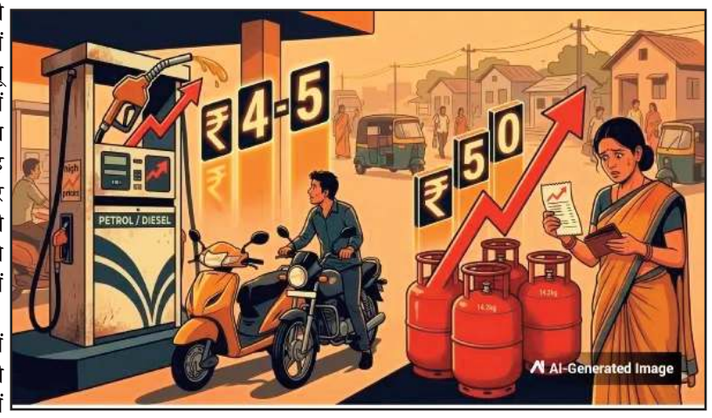

क्यों आ रहा है बढ़ोतरी का संकेत? पश्चिम एशिया तनाव ने बढ़ाई आग

मुख्य वजह पश्चिम एशिया में बढ़ता युद्ध तनाव है। ईरान-इजरायल संघर्ष, हार्मुज जलडमरूमध्य में संभावित आपूर्ति व्यवधान और लंबे समय तक अस्थिरता की चिंता ने ब्रेंट क्रूड को $107-110 प्रति बैरल (कुछ रिपोर्ट्स में $126 तक) पर पहुंचा दिया है। भारत अपनी 85% कच्चे तेल की जरूरत आयात पर निर्भर है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय कीमतों का सीधा असर पड़ रहा है।

तेल विपणन कंपनियां (IOC, BPCL, HPCL) भारी घाटे में हैं - पेट्रोल पर ₹14-24 प्रति लीटर और डीजल पर ₹18-100 प्रति लीटर का नुकसान। खुदरा कीमतें नहीं बढ़ने से उनकी आय प्रभावित हो रही है। सरकार पर सब्सिडी और टैक्स छूट का बोझ बढ़ रहा है। सूत्र बताते हैं कि आंतरिक विचार-विमर्श चल रहा है। सरकार तेल कंपनियों के दबाव को कम करना चाहती है, लेकिन मुद्रास्फीति को भी नियंत्रित रखना है।

भारत की मजबूत रणनीति - 'ऊर्जा सुरक्षा का ओएसिस'

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक संकटों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा-

आयात विविधीकरणः पहले भारत 27 देशों से तेल आयात करता था, अब यह संख्या 40 हो गई है। इससे सप्लाई का जोखिम कम हुआ।

एलपीजी उत्पादन में 60% बढ़ोतरीः रिफाइनरियों को निर्देश दिए गए। उत्पादन 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से बढ़कर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन हो गया।

'ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा': सरकार, कंपनियां और अंतरराष्ट्रीय सप्लायर्स का समन्वित प्रयास। संकट के समय भी सप्लाई चेन बरकरार रही।

तेल कंपनियों ने नुकसान उठायाः अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ने पर भी कंपनियों ने घाटा सहा ताकि आम उपभोक्ता पर बोझ न पड़े।

33 करोड़ घरों में एलपीजी सप्लाईः घरेलू किचन पर कोई असर नहीं। कमर्शियल एलपीजी अब संकट से पहले के स्तर का 70% पहुंच चुकी है।

रोजगार से जुड़े सेक्टरों को प्राथमिकताः स्टील, ऑटो, टेक्सटाइल, केमिकल और प्लास्टिक उद्योगों को गैस उपलब्ध कराई जा रही है।

पुरी ने कहा कि दुनिया जब-जब तेल संकट में फंसी, भारत ने पहले से तैयारी करके हालात संभाले। हम ऊर्जा सुरक्षा के मामले में 'ओएसिस' बने हुए हैं।

दूसरी ओर पाकिस्तान में स्थिति भयावह है। IMF दबाव में सरकार ने पेट्रोल को ढडफ 399.86 प्रति लीटर और डीजल को PKR 399.58 प्रति लीटर कर दिया है। यानी ₹400 पार। हाल ही में पेट्रोल में ढडफ6.51 और डीजल में PKR 19.39 की बढ़ोतरी हुई। पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें, पैनिक बाइंग और आम लोगों में आक्रोश है। भारत की तुलना में पाकिस्तान की स्थिति दिखाती है कि हमारी रणनीति कितनी मजबूत है।

आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा?

अगर बढ़ोतरी हुई तोः

दैनिक कम्यूटरः 50 लीटर टैंक भरने वाले को महीने में ₹250-300 अतिरिक्त खर्च।

ट्रांसपोर्ट और सामानः ट्रक-बस किराया बढ़ेगा, सब्जी-दूध-फल की कीमतें 2-5% तक चढ़ सकती हैं।

घरेलू LPGः ₹50 बढ़ोतरी पर सालाना 12 सिलेंडर भरने वाले परिवार को ₹600 ी७३१ं बोझ।

मुद्रास्फीतिः खासकर ग्रामीण और मध्यम वर्ग पर दबाव बढ़ेगा।

सरकार का संतुलनः क्या होगा अगला कदम?

सरकार कई विकल्प तौल रही है - सीधी बढ़ोतरी, सब्सिडी बढ़ाना या एक्साइज ड्यूटी घटाना। फैसला 5-7 दिनों में आने की संभावना है। अधिकारी कहते हैं कि लक्ष्य है तेल कंपनियों का घाटा कम करना, लेकिन मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखना।

भारत तैयार है, लेकिन सतर्कता जरूरी

यह फैसला सिर्फ पेट्रोल पंप या गैस सिलेंडर की कीमत नहीं, बल्कि पूरे अर्थव्यवस्था, मुद्रास्फीति और आम बजट को प्रभावित करेगा। हरदीप सिंह पुरी की रणनीति साबित करती है कि भारत ने ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया है, आयात विविधीकरण, घरेलू उत्पादन बढ़ावा और उपभोक्ता सुरक्षा। पाकिस्तान की तुलना में हम बेहतर स्थिति में हैं।

फिलहाल सरकार ने अफवाहों पर शांति बनाए रखने की अपील की है। आम आदमी को सलाह है कि पैनिक बाइंग न करें, ईंधन बचत अपनाएं - कारपूलिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और LPG का सही इस्तेमाल।

लापरवाही के बोझ से डूबा क्रूज? फ्री टिकट ने उलझाया आंकड़ों का गणित, 9 शव बरामद

(ªfeE³fEÅf)Ü

मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी डैम के बैक वॉटर में गुरुवार शाम हुआ क्रूज हादसा अब एक बड़ी मानवीय त्रासदी बन चुका है। 'नर्मदा क्वीन' नामक क्रूज तूफानी हवाओं और लहरों के बीच अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे ने जहां कई परिवारों को उम्र भर का गम दिया है, वहीं प्रशासन और पर्यटन विभाग की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

हादसे का शिकार हुई दिल्ली की संगीता कोरी ने मीडिया से बातचीत में जो बताया, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उनके मुताबिक, शाम करीब 9 बजे जब क्रूज वापस लौट रहा था, तभी अचानक मौसम बिगड़ा। तूफानी हवाओं के साथ पानी क्रूज के अंदर भरने लगा।

लाइफ जैकेट के लिए छीना-झपटी

संगीता का आरोप है कि किसी भी यात्री को लाइफ जैकेट नहीं पहनाई गई थी। जब क्रूज डूबने लगा, तब क्रूज स्टाफ ने स्टोर रूम से जैकेट निकालने की कोशिश की, जिससे यात्रियों के बीच जान बचाने के लिए छीना-झपटी मच गई।

लापरवाही और रेस्क्यू ऑपरेशन

शुरूआती जांच और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद क्रूज का संचालन किया गया। स्थानीय लोगों ने चालक को रुकने का इशारा किया था, लेकिन अनुभवहीनता और लापरवाही के चलते उसने क्रूज नहीं रोका। फिलहाल, आगरा से आई सेना की टीम और NDRF हाइड्रोलिक मशीनों और गैस कटर से क्रूज को काटकर शवों की तलाश कर रही है।

टिकट और यात्रियों की संख्या का 'सस्पेंस'

हादसे के वक्त क्रूज पर सवार यात्रियों की सही संख्या को लेकर अब भी गहरा सस्पेंस बना हुआ है। आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक, क्रूज पर 29 पर्यटक और 2 क्रू मेंबर्स

के होने की बात कही जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही इशारा कर रही है।

चश्मदीदों और स्थानीय सूत्रों के अनुसार, क्रूज पर सवार लोगों की संख्या 40 के पार हो सकती है। इस अंतर की बड़ी वजह यह है कि क्रूज पर 10 से 12 छोटे बच्चे भी मौजूद थे, जिनका 5 साल से कम उम्र होने के कारण टिकट नहीं लगा था और उनका कोई हेड-काउंट (गिनती) नहीं किया गया। इसके अलावा, कुछ लोगों को बिना टिकट या 'फ्री' में बैठाए जाने की आशंका ने भी प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

पर्यटन विभाग के रिसॉर्ट से महज 100 मीटर की दूरी पर हुए इस हादसे के बाद अब पूरे संचालन तंत्र पर सवाल उठ रहे हैं। मौके पर मौजूद मंत्रियों ने स्पष्ट किया है कि क्षमता से अधिक भार और सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गंभीरता से जांच की जाएगी।

कितनी होती है एक क्रूज की क्षमता?

बरगी बांध में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साल 2006 से क्रूज का संचालन किया जा रहा है। यहां 'नर्मदा क्वीन' जैसे दो प्रमुख क्रूज संचालित होते हैं, जिनमें एक हाउस बोट और एक मिनी क्रूज शामिल है। आमतौर पर एक क्रूज की क्षमता लगभग 60 से 90 पर्यटकों की बताई जाती है। यहां एक व्यक्ति के टिकट की कीमत करीब 200 से 220 रुपये है। हालांकि, हादसे का शिकार हुए क्रूज में क्षमता से अधिक या बिना रिकॉर्ड के लोगों का सवार होना एक बड़ी लापरवाही के रूप में सामने आ रहा है, जिसकी वजह से बचाव दल को अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में कितने लोग लापता हैं।

मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर राहत एवं बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी हैं। घटनास्थल पर मौजूद पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह और पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) की ओर से, जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।

आधिकारिक आंकड़ेः मृतक, लापता और जीवित बचे लोगों की लिस्ट

1. मृतकों की लिस्ट (पुष्टिः 06)

नीतू सोनी (उम्र 43), निवासीः जबलपुर, सोभाग्यम अलागन (उम्र 42), निवासीः तमिलनाडु, मधुर मैसी (उम्र 62), निवासीः दिल्ली, काकुलाझी (उम्र 38), निवासीः खमरिया, रेशमा सैय्यद (उम्र 66), शमीम नकवी (उम्र 66)

2. लापता व्यक्तियों की लिस्ट (संख्याः 09), तमिल (उम्र 5), पिताः कामराज, विराज सोनी (उम्र 6), मयूरम (उम्र 9), पूनम थापा (उम्र 7), ज्योति श्रीवास (उम्र 34), पतिः मनोज श्रीवास, त्रिशान/जहान (उम्र 4), पिताः प्रदीप मैसी, प्रदीप मैसी, मरिना मैसी, पतिः प्रदीप मैसी, कामराज (उम्र 39)

3. सकुशल बचे जीवित व्यक्तियों की सूची (कुलः 24), राखी सोनी (35 वर्ष), विक्की सोनी (विकास सोनी) (45 वर्ष), समृद्धि सोनी (18 वर्ष), इनिया (कल्लर्ट) (12 वर्ष), आराध्या सोनी (12 वर्ष), मोहित नामदेव (23 वर्ष), महेश पटेल, छोटे लाल गौड़ (38 वर्ष), अनामिका सोनी (47 वर्ष), रियाज हुसैन (72 वर्ष), के. पवीथारन (10 वर्ष), मनोज श्रीवास (40 वर्ष), अंशिका, तनिष्क (11 वर्ष), तनिष्का (10

एआई बना हेल्थ सेक्टर का नया गेमचेंजर, रेयर डिज़ीज़ की पहचान में चिकित्सकों से भी आगे, रिसर्च में दावा

(जीएनएस)।

आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी (AI) अब डॉक्टरों को भी टक्कर देती दिख रही है। मरीज की बीमारी पहचानने से लेकर इमरजेंसी में इलाज संभालने तक यह कई कामों में डॉक्टरों से बेहतर प्रदर्शन कर रही है या कर सकती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की साइंस में पब्लिश हुई एक रिसर्चमें पाया गया कि आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी कई मामलों में डॉक्टरों के बराबर या उनसे बेहतर काम कर सकती है।

इससे साफ है कि आने वाले समय में इलाज के तरीके में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना नया सिस्टम पेश किया है जो मुश्किल बीमारियों की पहचान में काफी मददगार बताया जा रहा है।

इमरजेंसी केस में भी अक रहा आगे

OpenAI का advanced AI मॉडल अब इमरजेंसी रूम में भी मरीज की हालत समझने में बेहतर काम कर रहा है। अक मरीजों के लिए जरूरी टेस्ट सुझाने से लेकर पूरे इलाज को संभालने में मदद कर रहा है। कई मामलों में अनुभवी डॉक्टरों के बराबर या उनसे बेहतर भी रिजल्ट दे चुका है।

रिसर्च में इस मॉडल को बोस्टन के एक अस्पताल के 76 इमरजेंसी केस पर इस्तेमाल किया गया। इसे तीन स्टेप में परखा और टेस्ट कियआ गया है। शुरूआत में मरीज की जांच, डॉक्टर से पहली मुलाकात और फिर मरीज को वार्ड या कउव में भेजने तक दो अलग-अलग डॉक्टरों ने बिना यह जाने कि जवाब अक का है या इंसान का इसका मूल्यांकन किया और पाया कि अकहर स्टेप में डॉक्टरों के बराबर या उनसे बेहतर रहा है।

अक ने सिर्फ केस स्टडी में ही नहीं बल्कि कम जानकारी और मुश्किल हालात में भी बीमारियों को पहचानने में अच्छा काम किया है। पुराने और जटिल केस जो कई सालों से टेस्ट के लिए इस्तेमाल होते आ रहे हैं, उनमें भी अक ने अच्छा रिजल्ट दिया है।

माइक्रोसॉफ्ट का नया अकसिस्टम MAI-DxO एक एडवांस टूल है जिसे मुश्किल बीमारियों की पहचान के लिए तैयार किया गया है और टेस्ट में इसने लगभग 85.5% मामलों में सही नतीजे दिए जबकि डॉक्टरों का स्कोर करीब 20% रहा।

यह सिस्टम एक अकेला अक नहीं है, बल्कि कई अकमॉडल की टीम की तरह काम करता है। जहां अलग-अलग AI मिलकर सवाल पूछते हैं, संभावित बीमारी पर चर्चा करते हैं, गलतियों को पकड़ते हैं और सही जांच चुनते हैं। इसे 'चेन ऑफ डिबेट'कहा जाता है।

इस तरीके से अक न सिर्फ ज्यादा सही डायग्नोसिस करता है बल्कि कम और जरूरी टेस्ट चुनकर खर्च भी कम करता है। हालांकि यह अभी सिर्फ रिसर्च स्तर पर है और अस्पतालों में इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं है इसके लिए आगे और टेस्टिंग, सेफ्टी चेक और सरकारी मंजूरी लेनी होगी।

क्या AI बन जाएगी नया डॉक्टर?

स्टडी के राइटर अर्जुन मनराई के मुताबिक यह रिसर्च सिर्फ लिखित जानकारी पर आधारित थी जबकि असली इलाज इससे कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। असल में डॉक्टर मरीज से सीधे बात करते हैं उसकी पूरी समस्या और लक्षण समझते हैं,-rÔy और ECG जैसी रिपोर्ट देखते हैं और मरीज की भावनाओं व हालात को भी ध्यान में रखते हैं कई बार इलाज सिर्फ रिपोर्ट के आधार पर नहीं बल्कि अनुभव और समझ से तय किया जाता है। जो अभी AI पूरी तरह नहीं कर सकता।

AI के पास जानकारी को तेजी से समझने और सुझाव देने की ताकत जरूर है लेकिन इंसानों जैसा अनुभव,भावनाओं और स्थिति के हिसाब से फैसला लेने की समझ अभी सीमित है। इसलिए इलाज के मामले में अंतिम फैसला हमेशा डॉक्टर ही लेते हैं जबकि अक एक असिस्टेंट के तौर पर काम करता है जो डॉक्टर को सही दिशा में मदद देता है।

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

सम्पादकीय

पाक की चालाकी के चलते ईरान को मिला अमेरिका की नाकेबन्दी का विकल्प

पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने का अभिनय तो कर ही रहा है साथ ही वह अमेरिका के होर्मुज समुद्री मार्ग में ईरान की नाकेबंदी से बचने के लिए तेहरान को 6 रास्ते दे दिए हैं ताकि वह अपना कच्चा तेल रूस और चीन को निर्बाध आपूर्ति कर सके। अब यदि ईरान के टैंकरों को अमेरिका की नाकेबन्दी का विकल्प मिल जाए तो भला ईरान क्यों झुकेगा। वह तो अमेरिकी दबाव का तमाशा बनाते हुए अपने तेल का निर्यात करेगा। दरअसल पाकिस्तान के कपटपूर्ण मैत्री का भण्डाफोड़ अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ डेरेक जी ग्रासमैन ने किया है। उन्होंने अमेरिका के ट्रंप प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान को जमीन के रास्ते मार्ग उपलब्ध कराकर पाकिस्तान ट्रंप की "अधिकतम दबाव" वाली रणनीति को कमजोर कर रहा है। ग्रासमैन ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट लिखा "ट्रंप प्रशासन आपके सामने एक समस्या है। आपका अच्छा दोस्त पाकिस्तान, ऐसा लगता है कि उसने अभी-अभी ईरान के लिए जमीन के रास्ते 6 मार्ग खोल दिए हैं। इससे ईरान की सरकार को होर्मुज में आपकी नाकेबंदी से बचने में मदद मिलेगी। इससे ईरान को अमेरिकी दबाव का सामना करते रहने में मदद मिलेगी। इस्लामाबाद एक बार फिर अमेरिका के साथ दोहरा खेल खेल रहा है।" पाकिस्तान को इस बात की कभी कोई परवाह नहीं रही कि उसे विश्व बिरादरी में किस दृष्टि से देख जा रहा है। एक तरफ वह ईरान के तेलों को चीन और रूस तक पहुंचाने के लिए अमेरिकी नाकेबन्दी को नाकाम करने में जुटा है तो दूसरी तरफ ईरान के दशतेस्तान क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले एवं ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विदेश नीति आयोग के प्रवक्ता ईब्राहिम रजाई ने एक तरफ तो इस्लामाबाद को अच्छा दोस्त बताया है लेकिन साथ ही इस बात पर भी जोर दिया है कि "वह मध्यस्थ के तौर पर उपयुक्त नहीं है।" रजाई ने यह खुलेआम आरोप लगाया कि पाकिस्तान पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाता है और अमेरिकी हितों को ज्यादा तरजीह देता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सुरक्षा विशेषज्ञ ग्रासमैन पाकिस्तान के इस दोहरे खेल को जान सकते हैं तो क्या अमेरिकी सीक्रेट एजेंसी इस वास्तविकता से अनिभिज्ञ है? कदापि नहीं, अमेरिका को ईरान एवं खाड़ी देशों में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी सीक्रेट एजेंसियां विस्तार से उपलब्ध कराती हैं। इस वक्त तो अमेरिका इतना घबराया हुआ है कि वह अपनी इज्जत बचाने के लिए सब वुछ करने को तैयार है जिसकी उसे कीमत न चुकानी पड़े क्योंकि अमेरिका को इस बात का एहसास हो चुका है कि जो दोस्त उन्होंने पाकिस्तान के रूप में चुना है, वह 'मक्कारी' का मास्टर माना जाता है। उसने अमेरिका से अफगानिस्तान में सोवियत सेना के खिलाफ लड़ने के नाम पर करोड़ों डालर ऐंठ लिया किन्तु उस वक्त उसने तालिबानी संगठनों को यह कहकर हथियार आपूर्ति नहीं की कि पाकिस्तान आमी तो अमेरिकी हथियारों को चलाने में काफी माहिर है। किन्तु तालिबानियों को इसकी कोई जानकारी नहीं है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया उल हक हथियारों के लिए जो अमेरिका से राशि लेता था उससे तो वह अपनी सेना को मजबूत करता था जबकि अमेरिका से भी धन भी ऐंठता था और एहसान भी जताता था कि उसने तो मुस्लिम देश के खिलाफ ही अपनी सेना भेजी है। इस तरह वह अमेरिका के लिए मीठा भी बना रहा तो वहीं दूसरी तरफ उसी को धोखा भी देता रहा। 2016 में ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान की कपटपूर्ण वूटनीति को समझकर उसको दिए जाने वाले सारे अनुदानों को बन्द कर दिया था। किन्तु दोबारा सत्ता में आते ही राष्ट्रपति ट्रंप पर फिर पाकिस्तान प्रेम का बुखार चढ़ा। अब जब खुद उन्हीं के देश को अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने की चुनौती खड़ी है तो वह उस पाकिस्तान पर आंख मूंदकर भरोसा करते दिखे जो आदतन दोहरे चरित्र का देश है और इसके नेता आदतन झूठे और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए मित्रता की सौदेबाजी करने के लिए वुख्यात हैं।

भारत को हिंद महासागर का 'रक्षक' बनाना चाहता है जापान, पहली बार दिया अभूतपूर्व ऑफर, निशाने पर चीन

जापान ने भारतीय नौसेना को मोगामी क्लास के महाशक्तिशाली युद्धपोत का ऑफर दिया है। यह युद्धपोत सबमरीन का शिकार करने में माहिर है। चीन के बढ़ते खतरे के बीच जापान ने पहली बार यह बड़ा कदम उठाया है जो भारत की ताकत को बढ़ाएगा।

टोक्यो: (जीएनएस)। जापान की सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए भारत को मोगामी क्ˆलास के युद्धपोत का ऑफर दिया है। जापान चाहता है कि उसकी तकनीकी मदद से भारत इस 50 करोड़ डॉलर के युद्धपोत को खुद से बनाए। यही नहीं जापान ने इस अपने सबसे घातक युद्धपोत को ऑस्ट्रेलिया को भी देना चाहता है। इन तीनों ही देशों का एक ही शत्रु है। वह है चीन। विश्लेषकों का कहना है कि अब तक रक्षात्मक रणनीति अपनाने वाला जापान अब खुलकर चीनी दादागिरी से निपटने में जुट गया है। इसी वजह से जापान ने भारत की नौसेना को यह अभूतपूर्व ऑफर दिया है। जापान चाहता है कि भारत हिंद महासागर में सुरक्षा मुहैया कराए। यही नहीं भारतीय नौसेना भी इस जापानी युद्धपोत की मुरीद है।

विश्ˆलेषकों का कहना है कि अगर भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया तीनों ही इस मोगामी क्लास के युद्धपोत का इस्तेमाल करते हैं तो इससे वे एक-दूसरे के पोर्ट पर इन्हें मरम्ˆमत भी आसानी से कर सकेंगे। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीनी ड्रैगन की नौसेना फुफकार रही है। चीन के युद्धपोत लगातार हिंद महासागर के रास्ते अफ्रीका के जिबूती तक चक्कर लगा रहे हैं। चीन की सबमरीन भी हिंद महासागर में आने लगी हैं। ऐसे में तीनों ही देशों के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। यह वही इलाका है जहां से जापान का ज्यादातर तेल गुजरता है। साथ ही दुनिया का सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्ग मलक्का स्ट्रेट भी यही पर है।

भारत दे हिंद महासागर में सुरक्षा, जापान का प्लान

इससे भारत को यह फायदा होगा कि वह इस अत्याधुनिक युद्धपोत को अपने यहां बना सकेगा। इससे भारतीय नौसेना की ताकत इतना ज्यादा बढ़ जाएगी कि वह आसानी से हिंद महासागर में 'सुरक्षा देने वाली' हो

जाएगी। जापान ने जो अपना ऑफर दिया है, उसमें मोगामी युद्धपोत का डिजाइन और उसे भारतीय शिपयार्ड में जापानी मटेरियल की मदद से बनाने में मदद करना शामिल है। एक मोगामी क्लास के युद्धपोत को बनाने में 50 करोड़ डॉलर का खर्च आएगा। इसे एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों तथा टारपीडो की मदद से लैस किया जा सकता है।

ऐसा पहली बार है जब जापान ने भारत को अपना कोई बहुत महत्वपूर्ण हथियार सिस्टम ऑफर किया है। वश्लिेषकों का कहना है कि यह ऑफर दिखाता है कि जापान रक्षा क्षेत्र में ज्यादा करीबी भागीदारी चाहता है। 21 अप्रैल को जापानी की कैबिनेट ने हथियारों के निर्यात और तकनीक को लेकर कड़े प्रतिबंधों को कम किया है। ऑस्ट्रेलिया के एडीलेड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पुर्णेंद्र जैन ने साऊथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट से बातचीत में कहा कि सह निर्माण का समझौता पीएम मोदी के 'मेक इन इंडिया' अभियान से मेल खाता है। इसके जरिए भारत अपने घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ाना चाहता है।

भारत का इरादा वैश्विक बाजार में अपने सपायरों में विविधता लाने का है। साथ अपने सैन्य आधुनिकीकरण को तेज करने का है।

प्रोफेसर पुर्णेंद्र जैन ऑस्ट्रेलिया के एडीलेड यूनिवर्सिटी

रूस से निर्भरत को घटा रहा है भारत

रिपोर्ट के मुताबिक भारत चाहता है कि उसकी आयात पर से निर्भरता कम हो जाए। भारत अपनी रूस पर से भी निर्भरता को कम करना चाहता है और इसी वजह से उसने हाल के वर्षों में फ्रांस, अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों से हथियारों का आयात बढ़ा रहा है। जैन ने बताया कि अभी आधिकारिक रूप से जापान ने अपना पूरा ऑफर नहीं दिया है। जेएनयू में जापानी अध्ययन के प्रोफेसर स्राबनी रॉय चौधरी ने कहा कि भारत की तटीय रेखा बहुत लंबी है। भारत को बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक अपने तटों की सुरक्षा करनी होती है। यह जापान के मुक्त और स्वतंत्र हिंद प्रशांत की संकल्पना के हिसाब से प्रासंगिक है।

जापान के मोगामी युद्धपोत की ताकत को जानें

मोगामी क्लास फ्रीगेट खासतौर पर एंटी सबमरीन युद्धकौशल के लिए बनाए गया है

जापानी युद्धपोत दुश्मन की सबमरीन को ट्रैक करता है, उसका शिकार करता है और रोकता है

यह युद्धपोत स्टील्थ तकनीक से लैस है जिससे दुश्ˆमन के रडार की पकड़ में नहीं आता है

मोगामी फ्रीगेट मल्टी मशिन युद्धपोत है जो हाई ऑटोमेशन के लिए डिजाइन किया गया है

जापानी युद्धपोत को चलाने के लिए केवल 90 नौसैनिकों की जरूरत होती है जो इसी तरह के युद्धपोत के लिए आधे से भी कम है

जापान और भारत दोनों मिलकर इसके वल्लूङ्ग१ल्ल रेडियो एंटेना को बनाने पर सहमत हुए हैं

जापान और ऑस्ˆट्रेलिया के बीच युद्धपोत के लिए 6.5 अरब डॉलर का समझौता हुआ है

भारत का फलोदी सट्टा बाजार हुआ पुराना, अमेरिका के पॉलीमार्केट ने बंगाल चुनाव पर की चौंकाने वाली भविष्यवाणी, आखिरी दौर में अचानक पलटा पासा

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दो चरणों के बाद सट्टा बाजार में जबरदस्त हलचल है. अब तक चर्चा में रहने वाले फलोदी सट्टा बाजार को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका के प्रेडिक्शन मार्केट 'पॉलीमार्केट' (ढङ्ग'ळ१'ी३) ने चौंकाने वाले आंकड़े जारी किए हैं. इस अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर बंगाल चुनाव को लेकर करीब 4.8 मिलियन डॉलर का दांव लग चुका है.जानें किस पार्टी को दे रहे हैं सत्ता. पश्चिम बंगाल की सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी, इसका फैसला तो चुनाव के नतीजे करेंगे, लेकिन सट्टा बाजार में अभी से बड़ा उलटफेर शुरू हो गया है. अब तक लोग केवल राजस्थान के फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़ों पर नजर टिकाए बैठे थे, लेकिन इस बार बंगाल के दंगल में सात समंदर पार अमेरिका के 'पॉलीमार्केट' ने तहलका मचा दिया है. मीडिया में छपी खबर के मुताबिक, अमेरिकी प्रेडिक्शन मार्केट में बंगाल चुनाव पर 4.8 मिलियन डॉलर से ज्यादा की ट्रेडिंग हो चुकी है. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दूसरे चरण के मतदान के बाद जीत-हार का पूरा गणित बदल गया है. जहाँ पहले ममता बनर्जी की टीएमसी को फेवरिट माना जा रहा था, वहीं अब विदेशी सट्टेबाज बीजेपी की जीत पर भारी दांव लगा रहे हैं. आंकड़ों की मानें तो बीजेपी की जीत की संभावना अब 56 फीसदी के पार निकल गई है, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है.

पॉलीमार्केट में बंगाल चुनाव का ग्लोबल क्रेज

अमेरिकी प्रेडिक्शन मार्केट पॉलीमार्केट पर बंगाल चुनाव को लेकर हो रही ट्रेडिंग ने सबको हैरान कर दिया है. वियॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्लेटफॉर्म पर निवेशक सीधे तौर पर अपनी राय और पैसा लगा रहे हैं. 29 अप्रैल 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, इस ऑनलाइन बाजार में करीब 4.8 मिलियन डॉलर का व्यापार बंगाल चुनाव के नतीजों पर हुआ है. यह पहली बार है जब किसी राज्य के चुनाव को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा आर्थिक दांव देखा जा रहा है. बाजार में बीजेपी की जीत की संभावना 56 प्रतिशत और टीएमसी की 43 प्रतिशत दिखाई जा रही है, जबकि अन्य दल 1 प्रतिशत से भी नीचे हैं.

दूसरे चरण के बाद ऐसे पलटी पूरी बाजी

इस चुनावी सट्टे में असली ट्विस्ट दूसरे चरण के मतदान के बाद आया है. अप्रैल की शुरूआत में इसी पॉलीमार्केट पर टीएमसी को 75-80 प्रतिशत के साथ सबसे मजबूत बताया जा रहा था, तब बीजेपी महज 20-25 प्रतिशत पर थी. लेकिन पहले चरण की वोटिंग के बाद यह आंकड़ा 54 प्रतिशत पर पहुंचा और दूसरे चरण की हिंसा और भारी मतदान के बाद बीजेपी अब 56 प्रतिशत के साथ सबसे आगे निकल गई है. यह ट्रेंड बताता है कि जैसे-जैसे वोटिंग बढ़ रही है, सट्टेबाजों का भरोसा बीजेपी की ओर शिफ्ट हो रहा है, जिसने बंगाल की सत्ता की लड़ाई को बेहद रोमांचक मोड़ पर खड़ा कर दिया है.

पॉलीमार्केट के डेटा का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि भले ही जीत की संभावना बीजेपी की ज्यादा दिख रही है, लेकिन ट्रेडिंग वॉल्यूम में टीएमसी अब भी काफी आगे है. रिपोर्ट के अनुसार, टीएमसी पर करीब 1.8 मिलियन डॉलर की ट्रेडिंग हुई है, जबकि बीजेपी पर यह आंकड़ा 1.1 मिलियन डॉलर है. विशेषज्ञों का मानना है कि टीएमसी पर ज्यादा वॉल्यूम होने का मतलब है कि कई लोग उसकी हार पर दांव लगा रहे हैं या फिर कुछ बड़े सट्टेबाज भारी रकम के साथ बाजार में उतार-चढ़ाव पैदा कर रहे हैं. यह विरोधाभास संकेत देता है कि बंगाल की जनता का मिजाज समझना इस बार सटोरियों के लिए भी टेढ़ी खीर है.

व्हेल ट्रेडर्स की एंट्री से मचा हड़कंप

सट्टा बाजार में 'व्हेल ट्रेडर्स' यानी उन बड़े खिलाड़ियों की एंट्री हो चुकी है जो लाखों डॉलर एक साथ निवेश करते हैं. रिपोर्ट में 'ङ१ङ्क२ल४ल्ल३१' नाम के एक प्रोफाइल का जिक्र है, जिसने बीजेपी की जीत के 'ी२' वाले 1,05,417 शेयर खरीदे हैं. इसका सीधा मतलब यह है कि अकेले इस खिलाड़ी ने बीजेपी की जीत पर 44 हजार से 60 हजार डॉलर के बीच दांव लगाया है. जब कोई बड़ा निवेशक इतनी मोटी रकम लगाता है, तो बाजार का पूरा समीकरण बदल जाता है. इसी वजह से बीजेपी का जीत प्रतिशत अचानक बढ़ गया है, जिसे लेकर सोशल मीडिया से लेकर न्यूज रूम्स तक चर्चा गर्म है.

दिल्ली और फलोदी सट्टा बाजार के अलग दावे

एक तरफ जहाँ अमेरिकी बाजार बीजेपी की लहर दिखा रहा है, वहीं दिल्ली और फलोदी के सट्टा बाजारों के आंकड़े थोड़े अलग हैं. दिल्ली सट्टा बाजार के मुताबिक, टीएमसी को 146-149 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी 140-143 सीटों के साथ कड़ी टक्कर दे रही है. भारतीय बाजारों में अभी भी मुकाबला बराबरी का माना जा रहा है. वियॉन की रिपोर्ट कहती है कि यह अंतर इसलिए भी हो सकता है क्योंकि पॉलीमार्केट में कई विदेशी निवेशक और वीपीएन का इस्तेमाल करने वाले भारतीय शामिल हैं, जिनकी सोच स्थानीय सट्टा बाजारों से अलग हो सकती है.

भारी मतदान के बीच कानूनी पेच और सट्टा

बंगाल में पहले दो चरणों में जो मतदान हुआ है, उसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. पहले चरण में 93.19% और दूसरे चरण में 91.41% वोटिंग ने विश्लेषकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है. पॉलीमार्केट जैसे प्लेटफॉर्म भारत में कानूनी तौर पर पेचीदा हैं, फिर भी क्रिप्टो और स्टेबलकॉइन्स के जरिए लोग जमकर रिस्क ले रहे हैं. सट्टेबाजों को लग रहा है कि यह भारी वोटिंग सत्ता परिवर्तन का संकेत है, और यही वजह है कि आखिरी दौर के आते-आते सट्टा बाजार में जीत-हार का पूरा समीकरण ही बदल गया है.

क्या सट्टा बाजार की भविष्यवाणी सच होगी?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सात समंदर पार बैठे सट्टेबाजों की यह भविष्यवाणी सच साबित होगी? वियॉन में प्रकाशित इस खबर ने बंगाल की राजनीति में एक नया नैरेटिव सेट कर दिया है. चुनाव के आखिरी चरणों तक यह आंकड़ा और भी बदल सकता है. लेकिन फिलहाल, पॉलीमार्केट के इस रुझान ने ममता बनर्जी के खेमे में चिंता और बीजेपी के खेमे में उत्साह पैदा कर दिया है. बंगाल का यह रण अब केवल बूथों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह वैश्विक वित्तीय बाजारों के दांव-पेंच का हिस्सा बन चुका है.

यह है हमारी अपनी हाइड्रोजन ट्रेन, दिल छू लेगी इसकी खासियत, पहली नजर में हो जाएगा इससे प्यार

(जीएनएस)।

हमारी अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल सफल रहा है. आज अपनी इस ट्रेन ने हरियाणा के जींद से सोनीपत के बीच रफ्तार भरी है. इस सफल ट्रायल के साथ हमारा देश भारत जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और चीन जैसे देशों की कतार में आ खड़ा हुआ है. हाइड्रोजन ट्रेन की इस सफलता के साथ भारत ने क्ˆलीन और ग्रीन टेक्ˆनोलॉजी की दिशा में नया कदम बढ़ा दिया है. क्ˆयोंकि, इस ट्रेन से न ही धुआं निकलता है और न ही प्रदूषण होता है. इससे सिर्फ पानी की भाप निकलता है. सबसे खासबात यह है कि इस ट्रेन के लिए विकसित की गई टेक्ˆनोलॉजी पूरी तरह से अपनी है. भारत में हाइड्रोजन ट्रेन, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, भारत में हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल, भारत में जीरो-एमिशन ट्रेन, ग्रीन

हाइड्रोजन ट्रेन, भारतीय रेलवे की हाइड्रोजन ट्रेन, 'मेक इन इंडिया' ट्रेन, हाइड्रोजन फ़्यूल ट्रेन के फायदे, जींद-सोनीपत हाइड्रोजन ट्रेन

सबसे शक्तिशाली इंजन क्षमता: इस ट्रेन का इंजन भी बहुत ताकतवर है. इसकी कुल क्षमता 2400 किलोवाट यानी करीब 3200 हॉर्सपावर है. दोनों पावर कार मिलकर ट्रेन को अच्छी रफ्तार और ताकत देती हैं. इससे ट्रेन भारी लोड और ज्यादा यात्रियों के साथ भी आसानी से चल सकती है.

यह ट्रेन पर्यावरण के लिए बिल्कुल सुरक्षित है. इसमें हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल होता है, जिससे धुआं या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती. सिर्फ पानी की भाप निकलती है, जो सेहत और पर्यावरण के लिए नुकसानदायक नहीं है.

इस ट्रेन का ट्रायल पूरी सुरक्षा के साथ किया गया. लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसे चलाकर देखा गया. ब्रेक, फ्यूल सिस्टम और बाकी सभी जरूरी चीजों की जांच की गई और सभी टेस्ट सफल रहे. सफल ट्रायल के बाद ग्रीन एनर्जी की तरफ भारत ने मजबूत कदम बढ़ा दिया है.

यह ट्रेन पूरी तरह भारत में बनी है. चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में इसे तैयार किया गया है. इसमें इस्तेमाल की गई तकनीक भी भारतीय इंजीनियरों की मेहनत का नतीजा है. यह 'मेक इन इंडिया' और आत्मनिर्भर भारत का बेहतरीन उदाहरण है.

इस हाइड्रोजन ट्रेन में एक साथ 2600 से ज्यादा यात्री सफर कर सकते हैं. इतनी बड़ी क्षमता इसे खास बनाती है. इससे ज्यादा लोगों को एक साथ सफर की सुविधा मिलेगी और भीड़भाड़ कम करने में भी मदद मिलेगी.

रितेश देशमुख का कमाल, छत्रपति शिवाजी महाराज पर बनी फिल्म का चला जादू

फल्म- राजा शिवाजी

स्टारकास्ट- रितेश देशमुख, संजय दत्त, सलमान खान, अभिषेक बच्चन

डायरेक्टर- रितेश देशमुख

रनटाइम- 3 घंटे 6 मिनट

स्टार- 4 (****)

छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ इतिहास का नाम नहीं बल्कि एक ऐसी भावना हैं जो खासकर महाराष्ट्र के लोगों के दिलों में गहराई से बसती है। इसी भावना को पर्दे पर उतारने का जिम्मा उठाया है बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख फ्ऱ्रीरँ ऊेरँ४ँ) ने और उन्होंने इसे सिर्फ निभाया ही नहीं बल्कि पूरी शिद्दत से जिया है।

'राजा शिवाजी' ने ऊंचा किया रितेश देशमुख का कद

फिल्म 'राजा शिवाजी' आज यानी 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस फिल्म में रितेश देशमुख सिर्फ एक अभिनेता के रूप में ही नहीं बल्कि लेखक और निर्देशक के तौर पर भी अपनी अलग पहचान छोड़ते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने राजा शिवाजी जैसे प्रोजेक्ट के जरिए अपने ही कद को और ऊंचा कर लिया है।

क्या है फिल्म 'राजा शिवाजी' की कहानी?

-फिल्म की कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन, उनके संघर्ष और स्वराज के लिए लड़ी गई ऐतिहासिक लड़ाई को बारीकी से पेश करती है। मराठा और मुगल साम्राज्य के बीच की राजनीति को जिस तरह से दशार्या गया है, वह दर्शकों को उस दौर में ले जाता है।

-ये फिल्म सिर्फ युद्ध के दृश्य नहीं दिखाती बल्कि शिवाजी महाराज की सोच, उनकी रणनीति और उनके नेतृत्व की गहराई को सामने लाती है। खासतौर पर उनकी युद्ध नीति, जिसमें दुश्मन के मनोबल पर पहले वार करना शामिल था, को बेहद प्रभावी ढंग से फिल्माया गया है।

दमदार रिसर्च और इमोशन का मेल है ये फिल्म

-फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी गहरी रिसर्च और मजबूत लेखन है। हर किरदार को कहानी में सही जगह दी गई है और ये साफ झलकता है कि इस प्रोजेक्ट पर कितनी मेहनत की गई है।

-रितेश देशमुख ने निर्देशक के तौर पर खुद को चमकाने की बजाय फिल्म को चमकाने पर ध्यान दिया है, जो उनकी समझदारी को दशार्ता है। फिल्म में शिवाजी महाराज के जीवन के कई ऐसे पहलू दिखाए गए हैं, जिनसे शायद बहुत से लोग अनजान होंगे।

-हालांकि विजुअल इफेक्ट्स

(श्न्न्र) कुछ जगहों पर और बेहतर हो सकते थे लेकिन कहानी की मजबूती और भावनात्मक जुड़ाव इन छोटी कमियों को नजरअंदाज करवा देता है।

फिल्म की दमदार स्टारकास्ट और उनकी एक्टिंग

-अभिनय के मामले में फिल्म बेहद मजबूत नजर आती है। रितेश देशमुख ने शिवाजी महाराज के किरदार को पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ निभाया है। उनका लुक, बॉडी लैंग्वेज और संवाद अदायगी किरदार के साथ पूरी तरह मेल खाती है। ये उनके करियर के बेहतरीन प्रदर्शन में से एक माना जा सकता है।

-सुपरस्टार सलमान खान का कैमियो फिल्म में एक अलग एनर्जी लेकर आता है। उनके स्क्रीन पर आते ही थिएटर में तालियों और सीटियों की गूंज सुनाई देती है।

-संजय दत्त अपने किरदार में बेहद प्रभावशाली नजर आते हैं। उनका खतरनाक अंदाज दर्शकों में गुस्सा और डर दोनों पैदा करता है, जो उनके अभिनय की सफलता है।

-अभिषेक बच्चन ने शिवाजी महाराज के बड़े भाई के किरदार में जान डाल दी है और लंबे समय बाद वह इतने प्रभावी लगे हैं। विद्या बालन ने भी अपने दमदार अभिनय से प्रभावित किया है। उनके किरदार की दृढ़ता और ताकत स्क्रीन पर साफ नजर आती है।

-इसके अलावा भाग्यश्री, जेनेलिया डिसूजा, अमोल गुप्ते, जितेंद्र जोशी, सचिन खेड़ेकर और बोमन ईरानी जैसे कलाकारों ने भी अपने-अपने किरदारों के साथ पूरा न्याय किया है।

राइटिंग और डायरेक्शन: फिल्म की असली ताकत

फिल्म की रीढ़ इसकी शानदार लेखनी है। रिसर्च और स्क्रिप्ट पर की गई मेहनत हर सीन में दिखाई देती है। निर्देशन के स्तर पर रितेश देशमुख ने कमाल कर दिया है। उन्होंने हर किरदार को संतुलित तरीके से पेश किया है और कहानी को प्रभावशाली बनाए रखा है। ये फिल्म उनके निर्देशन कौशल का बेहतरीन उदाहरण है।

म्यूजिक: अजय-अतुल का जादू

फिल्म का म्यूजिक अजय-अतुल (अ्रं८-अ३४') ने तैयार किया है, जो फिल्म की आत्मा बनकर उभरता है। बैकग्राउंड स्कोर और गानों में वो भावनात्मक ताकत है, जो कहानी को और प्रभावी बनाती है।

क्यों देखनी चाहिए फिल्म 'राजा शिवाजी'?

ये फिल्म सिर्फ एक ऐतिहासिक कहानी नहीं बल्कि एक अनुभव है। एक ऐसे महान योद्धा की कहानी, जिन्हें लोग भगवान के समान मानते हैं। अगर आप इतिहास, देशभक्ति और मजबूत कहानी वाली फिल्मों के शौकीन हैं, तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक एहसास है जिसे बड़े पर्दे पर महसूस करना ही सही मायनों में इसका आनंद लेना है।

लखनऊ में शनिवार दोपहर 3 बजे से इन इलाकों में वाहनों की होगी नो एंट्री, घर से निकलने से पहले देख लें डायवर्जन प्लान

लखनऊ के हजरतगंज इलाके में 'आक्रोश मशाल यात्रा' के कारण शनिवार दोपहर तीन बजे से बड़े और व्यावसायिक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

लखनऊ। (जीएनएस)। आक्रोश मशाल यात्रा को लेकर शनिवार को हजरतगंज इलाके में दोपहर तीन बजे से बड़े और कमर्शियल वाहनों की नो एंट्री रहेगी। कार्यक्रम समाप्ति तक डायवर्जन लागू रहेगा।

इसे लेकर यातायात विभाग की तरफ से डायवर्जन प्लान लागू किया गया है। आवश्यकता पड़ने पर आपात सेवाओं में लगे वाहनों को राहत दी जाएगी। जरूरत पड़ने पर लोग यातायात पुलिस की हेल्पलाइन 9454405155 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

यह रहेगी व्यवस्था

लाल बत्ती चौराहे की ओर से 1090 चौराहा, समतामूलक चौराहा, पॉलिटेक्निक चौराहा, सुभाष चौराहा, चौक की ओर जाने वाला सामान्य यातायात बंदरियाबाग चौराहा, गोल्फ क्लब चौराहा, राजभवन, डीएसओ चौराहा, हजरतगंज चौराहा, जीपीओ मोड़, विधानसभा की ओर प्रतिबंधित रहेगा।

यह यातायात लालबत्ती चौराहा से कटाईपुल चौराहा, जी-20 चौराहा (शहीदपथ), कमता तिराहा होकर अथवा कैंट होते हुए कुंवर जगदीश चौराहा, केकेसी तिराहा, बर्लिंगटन चौराहा, अशोकलाट कैसरबाग चौराहा की ओर से होकर जा सकेगा।

डीएसओ चौराहा, रायल होटल चौराहा की ओर से सुभाष चौराहा, सिकन्दरबाग चौराहा, महानगर, गोमतीनगर की तरफ जाने वाला सामान्य यातायात हजरतगंज विधानसभा मार्ग की ओर प्रतिबंधित रहेगा बल्कि यह यातायात लालबत्ती चौराहा से कटाईपुल चौराहा, जी-20 चौराहा (शहीदपथ), कमता तिराहा होकर अथवा कैण्ट होते हुए कुंवर जगदीश चौराहा, केकेसी तिराहा, बर्लिंगटन चौराहा, अशोकलाट कैसरबाग चौराहा की ओर से होकर जा सकेगा।

पार्क रोड की ओर से चारबाग, कैसरबाग, लालबत्ती की ओर जाने वाला सामान्य यातायात डीएसओ चौराहा, हजरतगंज चौराहा, विधानसभा की ओर प्रतिबंधित रहेगा।

यह यातायात पार्क रोड से दैनिक जागरण चौराहा, सिकन्दरबाग चौराहा, चिरैयाझील चौराहा, सुभाष चौराहा की ओर से होकर जा सकेगा।

गोमतीनगर की ओर से कैण्ट, चारबाग, आलमबाग, चौक की ओर जाने वाला सामान्य यातायात राजभवन, डीएसओ चौराहा, हजरतगंज चौराहा, जीपीओ मोड़, विधानसभा, सिसेंडी तिराहा की ओर प्रतिबंधित रहेगा, यह यातायात समतामूलक चौराहा से ग्रीन कॉरिडोर होकर डालीगंज चौराहा होते हुए अथवा गोल्फ क्लब चौराहा, बन्दरियाबाग चौराहा, लालबत्ती चौराहा, कैण्ट होकर जा सकेगा।

सिकन्दरबाग चौराहा की ओर से चारबाग, चौक, कैसरबाग की ओर जाने वाला सामान्य यातायात हजरतगंज, विधानसभा की ओर प्रतिबंधित रहेगा, यह यातायात सुशीला स्मृतिका ग्रीन कारिडोर चौराहा होकर ग्रीन कॉरिडोर, डालीगंज चौराहा, सीडीआरआई तिराहा होते हुए कैसरबाग, चारबाग, चौक को जा सकेंगी।

परिवर्तन चौक, हिन्दी संस्थान तिराहा की ओर से गोमतीनगर, कैंट, अर्जुनगंज बाजार एवं तेलीबाग, आलमबाग, कानपुर रोड की ओर जाने वाला सामान्य यातायात हजरतगंज चौराहा, विधानसभा की ओर प्रतिबंधित रहेगा, यह यातायात सुभाष चौराहा से ग्रीन कॉरिडोर अथवा चिरैयाझील, बैकुण्ठ धाम होकर अथवा अल्का तिराहा से डनलप तिराहा, सहारागंज तिराहा, सिकन्दरबाग चौराहा से समतामूलक चौराहा अथवा अशोक लाट चौराहा, बर्लिंग्टन चौराहा, केकेसी तिराहा होकर जा सकेगा।

तेलीबाग, बंगला बाजार से गोमतीनगर, महानगर की ओर जाने वाला सामान्य यातायात डीएसओ चौराहा, हजतरगंज की ओर प्रतिबंधित रहेगा, बल्कि यह यातायात बन्दरियाबाग चौराहा, गोल्फ क्लब चौराहा, 1090 चौराहा, समतामूलक चौराहा होकर जा सकेगा।

लालबाग चौराहा से महानगर, गोमतीनगर, कैंट की ओर जाने वाला सामान्य यातायात कैपिटल तिराहा की तरफ प्रतिबंधित रहेगा बल्कि यह यातायात मेफेयर तिराहा, सुभाष चौराहा, अल्का तिराहा, डनलप तिराहा, सिकन्दरबाग चौराहा, ग्रीन कॉरिडोर (सुशीला स्मुतिका चौराहा) होकर जा सकेगा।

चारबाग से महानगर, गोमतीनगर की ओर जाने वाला सामान्य यातायात बर्लिंग्टन चौराहा से बांये अशोक लाट चौराहा होते हुए सुभाष चौराहा, हनुमान सेतु (ग्रीन कॉरिडोर) होकर जा सकेगा।

रोडवेज, सिटी बसें जिन्हे संकल्प वाटिका पुल के नीचे तिराहा, महानगर की तरफ से चारबाग, कैसरबाग की ओर जाना है वह सिकन्दरबाग चौराहा, हजरतगंज चौराहा, विधानसभा की ओर प्रतिबंधित रहेंगी, बल्कि यह बसें सुशीला स्मृतिका ग्रीन कॉरिडोर चौराहा होकर ग्रीन कॉरिडोर, डालीगंज चौराहा, सीडीआरआई तिराहा होते हुए कैसरबाग, चारबाग को जा सकेंगी।

रोडवेज, सिटी बसें जिन्हे केकेसी तिराहा, चारबाग की ओर से गोमतीनगर, महानगर की ओर जाना है वह हुसैनगंज चौराहा, रायल होटल चौराहा, विधानसभा की ओर प्रतिबंधित रहेंगी, बल्कि यह बसें लोको चौराहा, कैंट, कटाईपुल चौराहा होकर गोमतीनगर एवं सुशांत गोल्फ सिटी की ओर जा सकेंगी तथा बर्लिंगटन चौराहा, अशोकलाट चौराहा, सुभाष चौराहा से डालीगंज पुल ग्रीन कॉरिडोर होकर महानगर, सीतापुर को वाहन जाएंगे।

रोडवेज, सिटी बसें जिन्हे गोमतीनगर की तरफ से चारबाग, कैसरबाग, चौक की ओर जाना है। वह सिकन्दरबाग चौराहा, हजरतगंज चौराहा, विधानसभा की ओर प्रतिबंधित रहेंगी, बल्कि यह बसें समतामूलक चौराहा, ग्रीन कॉरिडोर से डालीगंज चौराहा, सीडीआरआई तिराहा होते हुए कैसरबाग, चारबाग, चौक को जा सकेंगी।

'सोनम के लिए कानून खिलवाड़, अब मुझे-मेरे परिवार को मरवा देगी'

(जीएनएस)।

मई 2025 में इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शादी सोनम से हुई। हनीमून पर शिलांग-चेरापुंजी गए जोड़े का सफर महज कुछ दिनों में खून से रंग गया। राजा की लाश खाई में मिली। पुलिस ने सोनम पर आरोप लगाया कि उसने अपने कथित प्रेमी राज कुशवाहा और अन्य साथियों के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची। सोनम और राज समेत पांच मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुए।

अब अप्रैल 2026 के अंत में शिलांग कोर्ट ने सोनम को जमानत दे दी। वजह? शिलांग पुलिस की बड़ी चूक। गिरफ्तारी के समय सोनम को सही धाराएं और गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए गए। कोर्ट ने इसे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन माना। पीडित परिवार का आरोप है कि यह 'क्लेरिकल एरर' नहीं, बल्कि सोनम के परिवार की पावर और पैसे का खेल है। राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने एक मीडिया साक्षात्कार में परिवार का दर्द, पुलिस पर आरोप, सोनम परिवार के साथ धोखा और आगे की लड़ाई खुलकर बताया। साक्षात्कार के सवाल-जवाब से समझा जा सकता है इस परिवार का दर्द।

सवाल-1: विपिन जी, जब आपको पता चला कि सोनम रघुवंशी को जमानत मिल गई है, तो आपके और पूरे परिवार का रिएक्शन क्या था

विपिन रघुवंशीः सोमवार को जमानत हुई और मंगलवार को मुझे अचानक पता चला। मैंने खुद शिलांग पुलिस को फोन किया था कि सोनम के केस में क्या अपडेट है। उन्होंने बताया, 'कल ही जमानत हो गई।' न पुलिस ने हमें सूचित किया, न हमारा प्राइवेट वकील, न सरकारी वकील। सबने जानकारी छुपाई। जब मैंने वजह पूछी तो वकील ने कहा कि पुलिस की चूक के कारण सोनम को जमानत मिल गई। हमारी तो दुनिया ही हिल गई।

सवाल-2: केस की सुनवाई चल रही थी, तब आपके परिवार का कोई सदस्य कोर्ट में मौजूद नहीं था? जानकारी क्यों नहीं मिली?

विपिन रघुवंशीः बिल्कुल नहीं। शिलांग पुलिस या कोर्ट की तरफ से एक भी सूचना नहीं आई। हम इंदौर में बैठे थे। फोन करके पूछने पर ही पता चला। जमानत के दिन भी किसी ने नहीं बताया। बाद में जब पूछा तो हां-हूं में जवाब मिला। यह साफ धोखा था।

सवाल-3: अब खबरें आ रही हैं कि सोनम के कथित बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा को भी जमानत मिल सकती है। अगर ऐसा हुआ तो आपका अगला कदम क्या होगा?

विपिन रघुवंशीः हम हाईकोर्ट जाएंगे। सोनम की जमानत खारिज कराने की अपील दायर करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। एक-एक करके आरोपी छूटते जा रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं? राजा की तस्वीर देखकर हम कहते हैं कि भाई, तेरे कातिल अभी जिंदा घूम रहे हैं और हम शर्मिंदा हैं।

सवाल-4: शादी के समय आपको सोनम के पुराने प्रेम प्रसंग की कोई भनक नहीं लगी? पूरा परिवार मिलकर धोखा दे रहा था?

विपिन रघुवंशीः हां, हमें बिल्कुल नहीं पता था, उसके अफेयर के बारे में। सोनम के माता-पिता कहते थे, 'सोनम बहुत सीधी लड़की है, जो आप कहेंगे वही करेगी।' मर्डर के बाद वही माता-पिता मीडिया में कहने लगे, 'हमारी लड़की मन की करती है, जो ठान लेती है करके दिखाती है।' शुरू से झूठ बोला गया। सोनम का पूरा परिवार मिला हुआ है। उसकी मां तो मर्डर प्लानिंग में शामिल थी।

सवाल-5: आप इंदौर में रहते हैं, सोनम का परिवार भी वहीं है। अब जमानत के बाद कोई धमकी या समझौते का दबाव महसूस हो रहा है? परिवार को खतरा है?

विपिन रघुवंशीः अभी तक सीधी धमकी नहीं आई, लेकिन डर तो लगा हुआ है। सोनम छूट गई है। एक-एक करके आरोपी बाहर आ रहे हैं। 11 महीने में बाहर आने के बाद इनके मन में कानून का डर खत्म हो गया। पैसे की पावर दिखा दी। अब ये लोग हमें या हमारे परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुझे या मेरे परिवार को मरवा सकते हैं। इनके पास पावर है, बैकअप है। पुलिस इतनी बड़ी चूक कैसे कर सकती है? इतना हाई-प्रोफाइल केस होने के बाद भी मर्डर चार्जेस सही से नहीं लगाए गए। शिलांग पुलिस ने पूरा शिलांग और सरकार को बदनाम कर दिया।

सवाल-6: चार्जशीट या FIR आपको दिखाई गई? धाराएं क्या लगी थीं, इसकी जानकारी पहले क्यों नहीं दी गई?

विपिन रघुवंशीः चार्जशीट आज तक मुझे नहीं दी गई। मैंने कोर्ट में मांगी थी। चालान डायरेक्ट मेरा वकील मांग रहा था, लेकिन नहीं मिला। गोविंद सिंह (सोनम का भाई) को मिल जाता है, मुझे नहीं। राजा के लिए भी हमेशा धोखा ही हो रहा है। शादी के सारे वीडियो और फोटो गोविंद ने गायब करवा दिए। हमने अपनी तरफ से फोटोग्राफर रखा था, लेकिन वो भी गोविंद के घर के पास का था और उसने सब सामग्री गोविंद को सौंप दी। अब वो देने से मना कर रहा है क्योंकि डर रहा है।

सवाल-7: राजा की मां के लिए यह 11 महीने कितने मुश्किल रहे होंगे? उनका दर्द क्या था?

विपिन रघुवंशीः एक मां का दर्द सिर्फ मां ही समझ सकती है। 30 साल बेटे को पाला, पढ़ाया, शादी कराई। शादी के कुछ दिन बाद बेटा हमेशा के लिए चला गया।

सवाल-8: शिलांग में आप सोनम या राज से आमने-सामने मिले थे? अगर अब मिलने का मौका मिले तो क्या पूछेंगे?

विपिन रघुवंशीः आज तक कभी नहीं मिला। न सोनम से, न राज से, न आकाश-आनंद से। कोर्ट में सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंस पर देखा। वे हंस रहे थे, चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। अगर आमने-सामने मिलूं तो सिर्फ एक सवाल पूछूंगा कि मारने से तुम्हें क्या मिला? राजा की गलती क्या थी?

सवाल-9: सोनम के परिवार की तरफ से समझौते की कोई कोशिश हुई?

विपिन रघुवंशीः नहीं। शुरू में वे कहते थे, 'हमारी लड़की ने गलत किया, उसे सजा मिलनी चाहिए। हम उसे छुड़वाएंगे नहीं।' आज वही माता-पिता सोनम को छुपाकर रखे हुए हैं। ढोंग रंग दिखा दिए।

सवाल-10: रिश्ता कैसे पक्का हुआ था? शादी में राजा कितना एक्साइटेड था?

विपिन रघुवंशीः रघुवंशी समाज का एक ऐप था। उसी के जरिए राजा ने सोनम को पसंद किया। सोनम के माता-पिता घर आए, घर-बार देखा। सब ठीक लगा। राजा बहुत खुश था। कहता थाकि बेटी किसी की भी हो, उसकी खुशी-दुख में साथी बनना है। सोनम घर में कुछ दिन रही। हनीमून से पहले उसका व्यवहार सामान्य था। कोई शक नहीं हुआ।

सवाल-11: मुस्कान-साहिल केस में प्रेग्नेंट होने के बावजूद जमानत नहीं मिली, लेकिन यहां सोनम को मिल गई। न्याय व्यवस्था पर क्या कहना है?

विपिन रघुवंशीः मुस्कान के पास पैसे-पावर नहीं था। सोनम के माता-पिता के पास दोनों हैं। उन्होंने गलत तरीके से इस्तेमाल किया। पूरी देश को शर्मिंदा कर दिया।

सवाल-12: आगे क्या प्लान है? उइक जांच की मांग करेंगे?

विपिन रघुवंशीः हाईकोर्ट में अपील के साथ उइक जांच की मांग करेंगे। पुलिस की गलती सुधारने के लिए उइक जरूरी है ताकि सच्चाई सामने आए और सोनम को सजा मिले।

सवाल-13: अगर सजा देने का अधिकार आपके हाथ में होता तो सोनम और राज को क्या सजा देते?

विपिन रघुवंशीः सोनम ने राजा को जितना तड़पाया, वैसी ही मौत उसे मिलनी चाहिए थी। फांसी से भी ज्यादा। मारने से उसे क्या मिला? आज उसे डर ही नहीं रहा।

सवाल-14: देश की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं?

विपिन रघुवंशीः सोनम को कानून ने छोड़ दिया, लेकिन सच्चाई अभी बाकी है। अगर आप राजा को न्याय दिलाना चाहते हैं तो सोनम से कोई संबंध न रखें। जहां मिले, वहां उसे सजा दिलाने में मदद करें। हम लड़ते रहेंगे।

मई 2025 में एक नई-नई शादी ने ऐसा मोड़ लिया, जिसने सभी को चौंका दिया। 11 मई को राजा रघुवंशी की शादी सोनम से हुई थी। शादी के कुछ ही दिन बाद, 21 मई को दोनों हनीमून के लिए मेघालय के खूबसूरत शहर शिलॉन्ग पहुंचे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन 23 मई को अचानक दोनों लापता हो गए। करीब 10 दिन बाद पुलिस को एक गहरी खाई से राजा का शव मिला, जो बुरी तरह क्षत-विक्षत था। शरीर पर धारदार हथियार से कई वार किए गए थे, जिससे साफ था कि यह एक प्लान्ड मर्डर था। उस समय सोनम गायब थी, जिससे शक और गहरा गया।

बाद में सोनम ने उत्तर प्रदेश में पुलिस के सामने सरेंडर किया। पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए। सामने आया कि सोनम का राज कुशवाहा नाम के युवक से अफेयर था। प्लान के तहत सोनम ने राजा को घूमने के बहाने एक सुनसान जगह पर बुलाया, जहां पहले से उसके साथी मौजूद थे। वहीं, पर राजा पर दो चाकुओं से हमला किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। वारदात के बाद सोनम मौके से भाग निकली। पुलिस ने बाद में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

राजा रघुवंशी मर्डर केस अब कानूनी लड़ाई का नया चरण में पहुंच गया है।

पीडित परिवार हाईकोर्ट और CBI की मांग पर अड़ा है। सोनम की जमानत के बाद राज कुशवाहा की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हो रही है।

टोल पर खत्म होगी चिक-चिक! बिना रुके कटेगा पैसा, फास्ट टैग कैसे बनेगा हाईवे 'फ्यूचर प्लान'

(जीएनएस)।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले करोड़ों वाहन चालकों के लिए एक क्रांतिकारी और सुखद बदलाव होने जा रहा है। अब आपको टोल प्लाजा पर लंबी कतारों में लगने या अपनी गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 24 अप्रैल 2026 को इस दिशा में एक बड़ी घोषणा करते हुए बताया है कि इस साल दिसंबर तक देश के कई प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर बैरियर-फ्री टोलिंग प्रणाली की शुरूआत कर दी जाएगी।

सरकार का लक्ष्य सफर को इतना सुगम बनाना है कि चालक बिना ब्रेक लगाए अपनी मंजिल तक पहुँच सकें और टोल शुल्क का भुगतान पूरी तरह से ऑटोमैटिक तरीके से हो जाए।

फास्टैग और एआई का स्मार्ट संगम

सरकार जिस नई तकनीक को धरातल पर उतारने जा रही है, वह मुख्य रूप से फास्टैग (FASTag) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर आधारित है। वर्तमान व्यवस्था में टोल प्लाजा पर लगे बैरियर गाड़ी के रुकने और टैग के स्कैन होने के बाद ही खुलते हैं, लेकिन नई प्रणाली में इन भौतिक बैरियरों को हटा दिया जाएगा।

हाईवे पर उच्च क्षमता वाले एआई कैमरे और सेंसर लगाए जाएंगे जो तेज रफ्तार में गुजरती गाड़ी की नंबर प्लेट और उस पर लगे फास्टैग को स्कैन कर लेंगे।

जैसे ही आपकी गाड़ी इन निर्धारित बिंदुओं को पार करेगी, आपके लिंक किए गए बैंक खाते या वॉलेट से पैसा अपने आप कट जाएगा। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि ईंधन की खपत

भी कम होगी और हाईवे पर लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी।

क्या हैं टोल प्लाजा के नए नियमः क्या-क्या बदला?

हाईवे पर सफर सुगम बनाने के लिए सरकार ने नियमों को भी पहले से अधिक सख्त कर दिया है। यदि आप इन नियमों की अनदेखी करते हैं, तो आपको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती हैः

कैशलेस अनिवार्यः अब टोल केवल फास्टैग या UPI के जरिए ही दिया जा सकता है। कैश (नकद) का विकल्प धीरे-धीरे खत्म किया जा रहा है।

वैलिड फास्टैग न होने पर जुमार्नाः अगर आपकी गाड़ी पर वैलिड फास्टैग नहीं है या उसमें पर्याप्त बैलेंस नहीं है, तो आपको दोगुना या उससे भी भारी जुमार्ना भरना पड़ सकता है।

एंट्री पर रोकः गंभीर मामलों में या बार-बार नियम तोड़ने पर आपकी टोल प्लाजा में एंट्री भी रोकी जा सकती है।

वढक का विकल्पः टोल प्लाजा पर अब दफकोड भी लगाए जा रहे हैं। अगर फास्टैग काम नहीं कर रहा, तो आप इसे स्कैन करके वढकपेमेंट कर सकते हैं। हालांकि, नेटवर्क की समस्या होने पर इसमें देरी की जिम्मेदारी चालक की होगी।

नितिन गडकरी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट का लाभ उठाने और जुमार्ने से बचने के लिए यात्री पहले से तैयारी कर लेंः

फास्टैग रखें एक्टिवः सुनिश्चित करें कि आपका फास्टैग एक्टिव है और आपके बैंक खाते या केवाईसी (KYC) से पूरी तरह लिंक है।

बैलेंस चेक करेंः सफर शुरू करने से पहले चेक कर लें कि आपके फास्टैग वॉलेट में पर्याप्त बैलेंस है।

वर्किंग UPI ऐप्सः अपने फोन में Google Pay या PhonePe जैसे वर्किंग यूपीआई ऐप्स जरूर रखें ताकि इमरजेंसी में भुगतान किया जा सके।

टैग की सही स्थितिः फास्टैग को हमेशा अपनी गाड़ी की विंडशील्ड के बिल्कुल सेंटर में ऊपर की तरफ लगाएं, ताकि सेंसर उसे आसानी से स्कैन कर सकें।

डिजिटल दूरी पड़ सकती है भारी

इस नई और आधुनिक व्यवस्था के लागू होने से उन लोगों को शुरूआत में काफी परेशानी हो सकती है जो अभी भी डिजिटल पेमेंट से कतराते हैं या स्मार्टफोन का उपयोग नहीं करते हैं। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि आपके पास डिजिटल भुगतान का कोई साधन उपलब्ध नहीं है, तो न केवल जुमार्ना लगाया जाएगा बल्कि टोल प्लाजा के भीतर प्रवेश पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है। इस प्रणाली का मूल उद्देश्य पूरे देश के राजमार्ग नेटवर्क को कैशलेस बनाना है ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे और मानव हस्तक्षेप कम से कम हो।

यात्रा से पहले इन जरूरी सावधानियों का रखें ध्यान

किसी भी संभावित परेशानी या जुमार्ने से बचने के लिए वाहन चालकों को कुछ बुनियादी बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। सबसे पहले यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि आपकी गाड़ी पर लगा फास्टैग पूरी तरह से एक्टिव हो और वह आपके बैंक अकाउंट से सही ढंग से लिंक हो।

तकनीक के दौर में अपने फोन में हमेशा गूगल पे या फोनपे जैसे वर्किंग यूपीआई ऐप्स तैयार रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फास्टैग को हमेशा अपनी गाड़ी की विंडशील्ड के बिल्कुल केंद्र (सेंटर) में लगाएं, जिससे एआई सेंसरों को उसे स्कैन करने में कोई तकनीकी बाधा न आए।

ट्रंप ने इजरायल को भेजे 6500 टन हथियार, ईरान पर दोबारा हमले की तैयारी! क्या कहती रिपोर्ट?

(जीएनएस)।

इजरायल के रक्षा मंत्री Israel Katz ने चेतावनी दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो वेस्ट जेरूसलम को ईरान पर दोबारा हमले शुरू करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब इजरायल ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में अमेरिका ने उसे 6,500 टन गोला-बारूद और कई दूसरे मिलिट्री सामान भेजे हैं। इस मदद के पहुचने से ही दोबारा ईरान पर हमले के कयास तेज होने लगे हैं।

कौन-कौन से हथियार पहुंचे इजरायल?

इजरायल के रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि देश के Ashdod Port और Haifa Port पर दो मालवाहक जहाज पहुंचे हैं। इन जहाजों में भारी मात्रा में सैन्य सामान लाया गया। इन जहाजों में हजारों हवाई और जमीनी गोला-बारूद, सैन्य ट्रक, Joint Light Tactical Vehicle (JLTVs) और दूसरे अहम सैन्य उपकरण शामिल थे। इजरायल का कहना है कि इससे उसकी सैन्य क्षमता और मजबूत होगी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, इन हथियारों और इक्विपमेंट्स को सैकड़ों ट्रकों पर लादकर पूरे देश में मौजूद Israel Defense Forces (IDF) के ठिकानों तक पहुंचाया गया।

फरवरी से अब तक कितना सामान मिला?

इजरायल ने दावा किया कि 28 फरवरी को अमेरिका-इजरायल द्वारा ईरान पर हमले शुरू होने के बाद से अब तक उसे 403 एयरलिफ्ट और 10 सीलिफ्ट के जरिए कुल 115,600 टन से ज्यादा सैन्य इक्विपमेंट मिल चुके

हैं। यह आंकड़ा अमेरिकी समर्थन के स्तर को दिखाता है।

दोबारा हमले की आहट!

इजरायल का ये ऐलान उन मीडिया रिपोर्ट्स से मेल खाती है जिनमें दावा किया गया कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के प्रमुख Brad Cooper ने अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump को ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू करने की योजना के बारे में जानकारी दी है।

ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति

रिपोर्ट्स के मुताबिक इस योजना का मकसद ईरान पर दबाव बढ़ाना है ताकि तेहरान एक ऐसा शांति समझौता मान ले जो अमेरिका और इजरायल के लिए ज्यादा आसान हो। यानी सैन्य दबाव को कूटनीतिक सौदेबाजी के टूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है।

लास्ट अटैक

Fox News के मुताबिक, ब्रैड कूपर ने इस योजना को तेहरान के खिलाफ "Last Attack" (अंतिम प्रहार) बताया है। इसमें ईरान की बची हुई सैन्य संपत्तियों, टॉप लीडरशिप और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के लिए छोटे लेकिन बेहद शक्तिशाली हमलों की लहर शामिल हो सकती है।

लक्ष्य क्या होगा?

अगर यह योजना लागू होती है, तो मकसद ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करना या पूरी तरह खत्म करना हो सकता है। इसका मतलब है कि एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड सेंटर, हथियार भंडार और सैन्य ठिकाने प्रमुख निशाने बन सकते हैं।

बातचीत वाला रास्ता कहां गया?

United States और Iranके बीच संकट का कूटनीतिक समाधान निकालने की कोशिशें अब तक सफल नहीं हो पाई हैं। बातचीत जारी है, लेकिन कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। इसीलिए बातचीत के रास्ते के अब मिल नहीं रहे। साथ ही, दोनों पक्षों के बीच सबसे बड़े विवाद Strait of Hormuz का कंट्रोल और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बने हुए हैं। यही दो मुद्दे समाधान में सबसे बड़ी रुकावट माने जा रहे हैं।

मार्च में इंटरसेप्टर की कमी, IDF ने क्या बताया था?

मार्च के मध्य में रींङ्ग१ ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट किया था कि ईरान के जवाबी हमलों के बीच इजरायल के एयर डिफेंस इंटरसेप्टर तेजी से कम हो रहे थे। हालांकि Israel Defense Forces ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया था और कहा था कि उसकी रक्षा क्षमता कमजोर नहीं हुई है।

कूटनीति का समर्थन, लेकिन सैन्य चेतावनी भी

रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने गुरुवार को कहा कि वेस्ट जेरूसलम, वाशिंगटन के कूटनीतिक प्रयासों का समर्थन करता है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि ईरान फिर खतरा न बने, जल्द दोबारा कार्रवाई करनी पड़ सकती है।

ईरान ने भी दिया सख्त जवाब

उसी दिन Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) की एयरोस्पेस फोर्स के ब्रिगेडियर जनरल Seyed Majid Mousavi ने जवाबी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर फिर हमला हुआ तो तेहरान दर्दनाक, लंबे और दूरगामी हमलों से जवाब देगा।

पश्चिम एशिया में फिर बढ़ सकता है तनाव

दोनों तरफ से आई इन चेतावनियों ने साफ कर दिया है कि युद्धविराम के बावजूद हालात पूरी तरह शांत नहीं हैं। अगर बातचीत नाकाम रही, तो पश्चिम एशिया में फिर बड़ा सैन्य तनाव देखने को मिल सकता है।

बरगी डैम त्रासदी में ज्यादा जिम्मेदार कौन? सरकार या आप? जिम्मेदार क्यों नहीं देते जवाब?

(जीएनएस)।

ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसे जरा गौर से देखिए। ये महज एक तस्वीर नहीं है, ये आज के भारत का क्रूर आइना है। जबलपुर का बरगी डैम, जहां की लहरें आज कलकल की आवाज नहीं कर रहीं, बल्कि हमारी व्यवस्था के मुंह पर जोरदार तमाचा मार रही हैं। एक मां और उसका बच्चा पानी में बेजान तैरते हुए, ये मंजर देखकर क्या आपकी आत्मा कांपी? या फिर आप भी उस 'सिस्टम' का हिस्सा बन चुके हैं जिसकी संवेदनाएं मर चुकी हैं?

शून्य से नीचे की कीमत

आज के दौर में एक आम इंसान की ज़िंदगी की कीमत क्या है? अगर शून्य से नीचे कोई पैमाना होता, तो शायद वही हमारे जीवन का मूल्य होता। सरकारों के लिए आप केवल एक वोट हैं और जब चुनाव आते हैं, तो नेता आपके घर की दहलीज तक

झुक जाते हैं। लेकिन जब सुरक्षा की बात आती है, जब बुनियादी सुविधाओं की बात आती है, तो यही तंत्र शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर दबा लेता है। इससे पहले इंदौर में गंदा पानी पीने से 25 से ज्यादा लोग मारे गए लेकिन सरकार की वही टाला-मटोली अभी भी जारी है।

जी-हुजूरी की कीमत चुकाएंगे आप और हम

लेकिन साहब, सिर्फ. सरकारों को दोष देकर हम और आप बच नहीं सकते। इस बबार्दी में उतना ही हाथ उन 'लोगों' का भी है, जिन्होंने सवाल पूछना छोड़ दिया है। जो सुबह-शाम बस हुक्मरानों की आरती उतारने में मशगूल हैं।

सत्ता से सवाल पूछना जिम्मेदारी नहीं, नागरिकता का धर्म भी है। मगर अफसोस, आज का नागरिक 'जी-हुजूरी' को ही राष्ट्रवाद समझ बैठा है और सत्ता से सवाल को देशद्रोह घोषित कर देता है। याद रखिएगा, जब आप सत्ता से सवाल करना बंद कर देते हैं, तो व्यवस्था इतनी निरंकुश हो जाती है कि उसे बरगी डैम की लहरों में बहती इन लाशों से कोई फर्क नहीं पड़ता।